



मेरी सफलता का श्रेय सभी कन्नड़ लोगों के प्यार और विश्वास को जाता है.. @ नम्मा बेंगलूरु

Postal Regd.No. HQ/SD/523/2023-25 | बुधवार, 25 जून, 2025 | हैदराबाद और नई दिल्ली से प्रकाशित | website : <https://www.shubhlabhdaily.com> | संपादक : गोपाल अग्रवाल | पृष्ठ : 14 | मूल्य-6 रु. | वर्ष-7 | अंक-174

सिंधु जल संधि खत्म होने के बाद भारत ने लिखा विश्व बैंक को पत्र

किशनगंगा और रतले प्रोजेक्ट पर विवाद अब बेमानी

सूफी यायावर

भारत ने विश्व बैंक से कहा है कि सिंधु जल संधि के स्थगित होने के बाद रतले और किशनगंगा हाइड्रो-पावर प्रोजेक्ट से अड़ंगा हटा ले। विश्व बैंक के मिशेल लिनो को लिखे पत्र में भारत सरकार ने आग्रह किया है कि सिंधु जल संधि को स्थगित होने के बाद की स्थिति में विश्व बैंक रतले और किशनगंगा हाइड्रो-पावर विवाद को लेकर हरी अपनी कार्रवाई रोक दे। भारत के अनुरोध पर विश्व बैंक

ने पाकिस्तान के विचार मांगे, जिसका स्वाभाविक तौर पर इस्लामाबाद ने विरोध किया। विश्व बैंक के विशेषज्ञ मिशेल लिनो दो हाइड्रो-पावर से संबंधित 2022 के विवाद की सुनवाई कर रहे हैं। पहला किशनगंगा नदी पर है और दूसरा रतले है। यह चेनाब नदी पर है। फ्रांसीसी डैम इंजीनियर और हाल ही तक बड़े डैम पर इंटरनेशनल कमिशन के अध्यक्ष रहे मिशेल लिनो को वर्ल्ड बैंक द्वारा 13 अक्टूबर 2022 को सिंधु जल संधि के अनुच्छेद-9 और

संलग्नक-एफ के तहत नियुक्त किया गया था। मिशेल लिनो का दायित्व भारत और पाकिस्तान दोनों पक्षों को सुनना और यह तय करना है कि इन प्रोजेक्ट की डिजाइन संधि के हिसाब से है या नहीं। पाकिस्तान का दावा है कि भारत संधि का उल्लंघन कर रहा है। जबकि भारत सरकार ने औपचारिक रूप से मिशेल लिनो को सूचित कर दिया है कि सिंधु जल संधि ही खत्म है तो उस पर पाकिस्तान का कुछ भी कहना अप्रासंगिक है। भारत ने



दूसरे राज्यों से सिंधु का जल मोड़ने के लिए नहर की योजना तैयार

मिशेल लिनो से अनुरोध किया कि वह किशनगंगा और रतले विवादों से संबंधित सहमत वर्क प्रोग्राम को स्थगित कर दें। 2025 वर्क प्रोग्राम के मुताबिक, पाकिस्तान को 7 अगस्त तक भारत के रुख पर लिखित जवाब देना था। दोनों पक्षों के साथ तटस्थ विशेषज्ञ की चौथी बैठक 17 से 22 नवंबर के लिए तय की गई थी। बदली हुई स्थिति में भारत सरकार ने कहा है कि मिशेल लिनो से यह उम्मीद की जाती है कि वे कार्यवाही को रोकने के बारे में

विचार करेंगे। सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद भारत सरकार का यह पहला पत्र है जो विश्व बैंक को लिखा गया है। इसके पहले भारत ने 24 अप्रैल को संधि को स्थगित रखने के अपने फैसले के बारे में औपचारिक रूप से पाकिस्तान को जानकारी दी थी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के पहले 7 मई को अपना जवाब दिया और दिल्ली की चिंताओं पर चर्चा करने की इच्छा का संकेत दिया। पाकिस्तान ने बातचीत के लिए मई में एक तारीख निर्धारित करने

का सुझाव भी दिया। लेकिन इस बीच ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया और भारत ने पाकिस्तान के पुराने प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया। नई दिल्ली फिलहाल इस मामले पर इस्लामाबाद के साथ बातचीत करने के लिए इच्छुक नहीं है। भारत सरकार ने बाकायदा यह घोषणा कर रखी है सिंधु जल संधि फिलहाल स्थगित रहेगी। इस बीच, भारत सरकार ने सिंधु नदी प्रणाली के जल को अलग-अलग भारतीय राज्यों में मोड़ने के लिए एक **10**र

ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में सैन्य आत्मनिर्भरता पर बोले पीएम मोदी

आतंकियों के लिए अब कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं

नई दिल्ली, 24 जून (एजेंसियां)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि रक्षा आवश्यकताओं के लिए भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इसका प्रभाव देखा है। हमारी सेनाओं ने मेड इन इंडिया हथियारों की मदद से 22 मिनट में दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियार दुनिया भर में जाने जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वालों के लिए कोई भी ठिकाना



भारत सरकार ने 2000 करोड़ की रक्षा खरीद मंजूर की

सुरक्षित नहीं है। देशहित में जो सही होता है आज का भारत उसके हिसाब से कदम उठाता है। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना को अत्याधुनिक हथियारों से लैस

करने की नीति के तहत भारत सरकार ने 2000 करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। सेना के आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए रिमोटली पायलेटेड एरियल व्हीकल, कई तरह के ड्रॉन्स, बैलिस्टिक हेलमेट, भारी और मध्यम रेंज के क्लिक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल और राइफलों के लिए नाइट विजन वगैरह खरीदे जाएंगे। यह रक्षा खरीद आपात अधिग्रहण व्यवस्था के तहत की जा रही है। इस रक्षा खरीद के तहत 13 कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई है। जिसमें सुरक्षाबलों के लिए आधुनिक हथियार और उपकरण खरीदे जाएंगे, जो आतंकवाद के खिलाफ हमारे सुरक्षाबलों की क्षमताओं में उल्लेखनीय इजाफा करेंगे।

10र

एससीओ समिट : भारत के एनएसए अजित डोभाल चीन पहुंचे

आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान



चीन के उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री एवं अन्य नेताओं से मिले डोभाल

बीजिंग, 24 जून (एजेंसियां)।

चीन की राजधानी बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक होने जा रही है। एससीओ की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। उससे पहले वहां एससीओ के सुरक्षा परिषद सचिवों की बैठक चल रही है। इसमें भाग लेने के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल भी बीजिंग में हैं। अजित डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान ज़ेंग और विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष

मुलाकात की। दोनों के साथ हुई वार्ता न केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से, बल्कि व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में ईरान-इजराइल युद्ध गहराता जा रहा है और वैश्विक शक्तियां क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

चीन में एसएसओ की सुरक्षा परिषद के सचिवों की 20वीं बैठक में एनएसए अजित डोभाल ने चीन के उप राष्ट्रपति हान ज़ेंग और अन्य कई प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से मुलाकात की। यह मुलाकात बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल में हुई, जहां शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की सुरक्षा परिषद के सचिवों की 20वीं बैठक हो रही है। चीन में भारतीय दूतावास ने जानकारी दी कि डोभाल इस बैठक में शामिल अन्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ हान ज़ेंग से मिलने पहुंचे थे।

एससीओ में डोभाल ने कहा, सीमापार आतंकवाद फैलाने वाले अपराधियों, साजिशकर्ताओं और उनका वित्तपोषण करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

10र

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा

बिहार में लगेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट



पटना, 24 जून (एजेंसियां)।

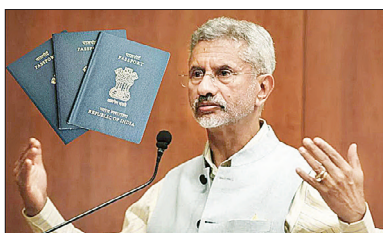
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने देश की ऊर्जा स्थिति और भविष्य की योजनाओं को लेकर यह घोषणा की कि बिहार में जल्दी ही एक न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए औपचारिक सहमति दे दी है। राजधानी पटना स्थित होटल ताज में मंगलवार को पांचवीं क्षेत्रीय ऊर्जा बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बिहार के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। ऊर्जा क्षेत्र में बिहार अब अग्रणी राज्यों की कतार में खड़ा है। इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ा है। उन्होंने बिहार में 80 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाने की कामयाबी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह एक रिकॉर्ड है। बिहार बिजली के क्षेत्र में पिछड़ माना जाता था, लेकिन आज काफी आगे बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि बिहार से न्यूक्लियर पावर प्लांट की मांग की गई है। बिहार सरकार न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए, हम उसमें मदद करेंगे। **10**र

देशभर में पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम का दूसरा सत्र शुरू

नई दिल्ली, 24 जून (एजेंसियां)।

देशभर में पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम का दूसरा सत्र शुरू होने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ई-पासपोर्ट रोलआउट का भी ऐलान किया है। विदेश मंत्री ने पासपोर्ट संबंधी कामकाज से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा, मैं पासपोर्ट कार्यालयों (पीओ), पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीएसके), डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) और पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के सभी भागीदारों को उनके समर्पण के लिए बधाई देता हूँ।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को 13वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश के पासपोर्ट अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (पीएसपी)



जयशंकर ने ई-पासपोर्ट रोलआउट का भी किया ऐलान

के अगले चरण और देशव्यापी ई-पासपोर्ट सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 13वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश में सभी पासपोर्ट अधिकारियों को बधाई दी।

उन्होंने लिखा, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मार्गदर्शन में आपके सराहनीय प्रयास यात्रा को आसान बनाने, वैश्विक कार्यस्थल तक पहुंच को गहरा करने और नागरिकों को सशक्त बनाने में सहायक हैं। पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 और ई-पासपोर्ट की शुरुआत के साथ विदेश मंत्रालय हमारी पासपोर्ट सेवाओं की समयबद्धता, पारदर्शिता और पहुंच को पहले बेहतर बेहतर बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। जयशंकर ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के स्तंभों के तहत पासपोर्ट सेवाओं में हुए बदलाव पर जोर दिया। उन्होंने इसे विकसित भारत के लक्ष्य को पाने का केंद्रीय जरिया बताया। उन्होंने कहा, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण शासन के **10**र

अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक ईमानदारी का बेजोड़ उदाहरण

देवी-देवताओं को गाली देने वाले को गिरफ्तार न करें

नई दिल्ली, 24 जून (एजेंसियां)।

हिंदू देवी देवताओं पर अश्लील टिप्पणी करने वाले और हिंदू महिलाओं का सिर तन से जुड़ा करने से लेकर बलात्कार करने तक की धमकियां देने वाले वजाहत खान की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा कर देश के सामने न्यायिक ईमानदारी की मिसाल पेश की है। यह वही वजाहत खान है जिसने शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ कोलकाता में केस दर्ज कराया और कोलकाता पुलिस उस 20 साल की छात्रा को गुरुराम से घसीटकर कोलकाता ले गई। शर्मिष्ठा का कसूर यह था कि पहलगाम हमले में हिंदुओं को चुन-चुन कर मारे जाने की घटना की सोशल मीडिया पर प्रशंसा कर रहे धर्मांधों को उसने कड़ाई से जवाब दिया था। **10**र



20 साल की छात्रा शर्मिष्ठा को भले ही घसीट ले जाए पुलिस

सर्पा बाज़ार



(24 कैरेट गोल्ड)

सोना : 99,680/-
(प्रति 10 ग्राम)
चाँदी : 1,07,930/-
(प्रति किलोग्राम)

मौसम बेंगलूरु

अधिकतम : 30°
न्यूनतम : 22°

भारतीय लोकतंत्र में मिसाल है जन-प्रतिनिधियों का दोहरापन

भ्रष्ट जज को बचाने और देशभक्त जज को मिटाने पर लगे

भारत के जन-प्रतिनिधियों का दोहरापन भारतीय लोकतंत्र के लिए अभूतपूर्व मिसाल है। इसी

स्वार्थ साधना बर रह गया है। विपक्ष का असली एजेंडा सत्ता के खिलाफ हंगामा और वोट

शुभ-लाभ तिमर्श

चारित्रिक प्रदूषण के कारण भारत की सियासत भीषण बदबूदार हो गई है। जनप्रतिनिधियों का यह दोहरापन दिखाता है कि राजनीतिक दलों को भ्रष्टाचार या न्यायपालिका के सुधार से कोई मतलब नहीं। बस बात-बेबात सरकार को घेरना, कोसना और अपना ओछा

बैंक की घटिया राजनीति है। भारतीय राजनीति में इन दिनों दोहरे मापदंडों का गंगा नृत्य चल रहा है। इस गंगा-नृत्य के मुख्य किरदार हैं विपक्षी सांसद, जो अपनी सुविधा के हिसाब से मुद्दों को उधारते और छुपाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव और



जस्टिस यशवंत वर्मा के मामलों में विपक्ष का रवैया विपक्षी सांसदों के गंदे चरित्र को साफ-साफ उजागर करता है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे यशवंत वर्मा

के घर से नोटों का जखीरा मिलने के बावजूद विपक्षी उस भ्रष्ट जज को बचाने में लगे हैं। वे हर कोशिश कर रहे हैं कि यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद

में महाभियोग न चलने पाए। दूसरी तरफ वही सांसद इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की आवश्यकता पर सार्वजनिक बयान दिया था। भ्रष्ट

नोट वाले जज बच जाएं

यूसीसी के पक्षधर जज नप जाएं

शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए अपना सतीत्व बेचने तक पर उतारू हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव की गलती क्या है? उनकी गलती यह है कि उन्होंने सम्पूर्ण भारतवर्ष में

आचरण और स्पष्ट बयान... इन दो चारित्रिक विभाजक रेखाओं में से विपक्षी सांसद पूरी निर्लज्जता से भ्रष्ट आचरण के पक्ष में खड़े हैं। विडंबना है कि भ्रष्ट जज यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार **10**र

कार्टून कॉर्नर

जैसे तुम संसदों में कोरोना फैल रहा है, वैसे ही हमारे संसदों में कोरोना फैल रहा है...





रचनात्मक शिक्षा के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना उद्देश्य

जीतो यूथ विंग बेंगलूरु साउथ की लाइट्स कैमरा, रील्स कार्यशाला का आयोजन

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

जीतो यूथ विंग बेंगलूरु साउथ ने जीतो सेंटर फॉर एक्सीलेंस के तहत एक गतिशील सात-दिवसीय कार्यशाला लाइट्स, कैमरा, रील्स का आयोजन किया, जो जीतो कार्यालय, चामराजपेट में आयोजित की गई। यह कार्यशाला 16 जून से 21 जून तक चली।

42 उत्साही प्रतिभागियों को आठ टीमों में विभाजित किया गया और उन्हें कई अंतर्दृष्टिपूर्ण खंडों और रचनात्मक चुनौतियों के माध्यम से व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला ने उन्हें आकर्षक शॉट-फॉर्म सामग्री बनाने के लिए उपकरण और तकनीक से लैस किया, प्रवृत्तियों, कैमरा तकनीक, प्रारूपों और दर्शक-केंद्रित कहानी कहने की व्यापक समझ प्रदान की। कार्यशाला की शुरुआत नवकार मंत्र के पाठ और जीतो यूथ विंग के गणमान्यों और प्रशिक्षकों द्वारा



दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जो छह दिनों के लिए एक सकारात्मक स्वर निर्धारित करती है।

जीतो यूथ विंग के चेयरमैन मेहुल श्रीश्रीमाल ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और कहा कि यह कार्यशाला विशेष रूप से युवाओं के लिए डिजाइन की गई है जो कल का भविष्य हैं। मुख्य सचिव ऋषभ चोपड़ा ने उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत किया

और अपने उद्घाटन भाषण के साथ कार्यक्रम के लिए एक आमंत्रित स्वर निर्धारित किया। संयोजक निधि मेहता और हर्षा जैन सह-संयोजक ने प्रशिक्षकों का परिचय दिया।

कार्यशाला के प्रशिक्षक विक्रम भंसाली, निधि श्रीश्रीमल और गौरव गुलेचा थे, जिन्होंने प्रतिभागियों को रील बनाने के विभिन्न पहलुओं के माध्यम से निर्देशित किया। कार्यशाला की

पांच-दिवसीय यात्रा रचनात्मक सीखने के अनुभवों से भरी हुई थी। प्रतिभागियों ने ध्वनि, शूटिंग और उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित किया, बुनियादी फोन वीडियोग्राफी में महारत हासिल की और कैमरे में आत्मविश्वास हासिल किया। उन्होंने मूवमेंट, ट्रांजिशन और कहानी-संचालित शॉट्स का अभ्यास किया, जो ट्रेंड रिक्रिएशन चैलेंज में परिणत हुआ। उन्होंने अपनी रचनात्मकता को

बाहरी रूप से लागू किया, प्रकाश और मूवमेंट जैसी सौंदर्य तकनीकों का उपयोग करके विभिन्न शैलियों में रील्स शूट किए। प्रतिभागियों ने मूल्य-चालित सामग्री, उत्पाद विज्ञापन और प्रशंसापत्र तैयार करना सीखा, विविध प्रारूपों का अभ्यास किया, जिसमें पॉडकास्ट-शैली के खंड शामिल थे। उन्होंने अपनी रील्स को रिटेशन रणनीति और प्रकाशन रणनीतियों के माध्यम से वायरल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, अंतिम बूटकैप यात्रा रील्स बनाई और रिल चैलेंज में एक सहयोगी रील में योगदान दिया।

कार्यक्रम एक रनातक समारोह के साथ समाप्त हुआ, जहां प्रतिभागियों ने अपने अंतिम प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए और प्रमाण पत्र प्राप्त किए। यूथ विंग मैनेजिंग कमिटी के सदस्य रोशनी जैन, रिद्धि मांडोट, रीथ, तक्ष जैन, शशांक खांडेड, कनीष बलार और राजश्वरी भी उपस्थित थे।

हमारी संस्कृति हमारे संस्कार विषय पर ज्ञानशाला सेमिनार



बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

बीज को जैसी जमीन और वातावरण मिलता है वैसा ही वह फलवान बनता है। ठीक इसी तरह बच्चों को जैसे संस्कार मिलते हैं वैसे ही वह विकास करता है। उपरोक्त विचार डॉ. मुनि पुलकित कुमार जी ने हमारी संस्कृति हमारे संस्कार विषय पर तैरापंथ भवन में राजाजी नगर ज्ञानशाला सेमिनार को संबोधित करते हुए कहे। मुनि ने आगे कहा बीज बोना आसान है पर संस्कार रूपी खाद पानी देना भी जरूरी है। आचार्य श्री महाश्रमण जी भी ज्ञानशाला के विद्यार्थियों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करते हैं क्योंकि बच्चे होनहार बनकर परिवार का, समाज का और देश का गौरव

बढ़ाते हैं। मुनि ने ज्ञानशाला प्रशिक्षकों को भी निर्जरा भाव से ज्ञान दान की सेवा देने के लिए साधुवाद दिया।

प्रश्नोत्तर सत्र में मुनि ने 25 बोल आदि पर बच्चों से प्रश्न पूछे जिसके उत्साह पूर्वक विद्यार्थियों ने उत्तर दिए। कंठस्थ ज्ञान प्रस्तुति सत्र में जिनीषा भंडारी, सानवी गन्ना ने शक्र स्तुति तथा लोगस्स पाठ गरिमा नाहर, प्रिया कोठारी, खुशबू जैन, कनक लोढ़ा ने प्रस्तुत किया।

तुलसी अष्टम अवधि मंथन बाफना तथा मंथन गादिया ने प्रस्तुत किया। नचिकेता आदित्य मुनि ने घर घर जागे सद संस्कार ज्ञानशाला का यह उपहार गीत के माध्यम से प्रेरणा दी। ज्ञानशाला

सेमिनार में मंगलाचरण ज्ञानशाला के बच्चों द्वारा अहम फल से हुआ। ज्ञानशाला कर्नाटक आंचलिक संयोजक मानक संचेती, राजाजीनगर तैरापंथ सभा अध्यक्ष अशोक चौधरी ने वक्तव्य दिया। आभार जापान वंदना कोठारी ने तथा संचालन ज्ञानशाला संयोजिका चेतना बेदमुथा ने व्यक्त किया। ज्ञानार्थी बच्चों को रोशन लाल कोठारी परिवार की तरफ से पारितोषिक वितरित किए गए। शिशु संस्कार बोध ज्ञानार्थी बच्चों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रकाश लोढ़ा, नीता गादिया, मंजू गन्ना, शांतिलाल पितलिया, चंद्रेश मांडोट, जगुराज श्रीश्रीमाल, लता गांधी आदि उपस्थित थे।

विक्रम महेर बने तैरापंथ युवक परिषद राजराजेश्वरीनगर के अध्यक्ष

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

अखिल भारतीय तैरापंथ युवक परिषद के निर्देशानुसार तैरापंथ युवक परिषद, राजराजेश्वरी नगर की अष्टम वार्षिक साधारण सभा अध्यक्ष विकास छाजेड़ की अध्यक्षता में तैरापंथ भवन राजराजेश्वरी नगर में आयोजित की गई। सामूहिक नवकार मंत्र द्वारा मंगलाचरण कर वार्षिक साधारण सभा की शुरुआत की गई। विजय गीत का संगान तुलसी संगीत सुधा के साथियों द्वारा किया गया। श्रावक निष्ठा पत्र का वाचन अखिल भारतीय तैरापंथ युवक परिषद के सीपीस के राष्ट्रीय प्रभारी दिनेश मरोठी ने किया। तैयुप राजराजेश्वरी नगर के अध्यक्ष बिकास छाजेड़ ने सभी का स्वागत अभिनन्दन करते हुए गत वर्ष में कार्यकर्ताओं द्वारा मिले सहयोग की सराहना की।



मंत्री सुपार्श पटवारी ने मंत्री प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए सत्र 2024-25 के कार्यकाल में किए गए कार्यों का उल्लेख किया व सभी के सहयोग के लिए आभार ज्ञापित किया। कोषाध्यक्ष गौतम नाहटा ने सत्र 24-25 में हुए आय-व्यय के बारे में जानकारी साझा किया। आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर के संयोजक नरेश बाँठिया ने वर्ष भर

में किए गए कार्यों एवं नए एटीडीसी की जानकारी प्रदान की तथा दोनों एटीडीसी के आय व्यय की जानकारी दी। कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तैयुप राजराजेश्वरी नगर सदस्यों द्वारा गत कार्यकाल में किये गये कार्य के लिए उन्हें उत्कृष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 2025-26 के अंकेक्षक के लिए

सी.ए. गणपत कोठारी के नाम की स्वीकृति लेकर उन्हें नियुक्त किया गया। दूसरे सत्र में वर्तमान कमिटी को भंग कर मंच चुनाव अधिकारी मनोज डागा एवं सह चुनाव अधिकारी राजेश भंसाली को सौंप दिया गया। चुनाव अधिकारी मनोज डागा ने अध्यक्ष पद हेतु एक ही नामांकन पत्र विक्रम महेर के नाम का प्राप्त हुआ है, ये जानकारी दी और विक्रम महेर को अध्यक्ष घोषणा किया। नवमनोनीत अध्यक्ष विक्रम महेर ने सभी का आभार व्यक्त किया और युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि संघ का काम हो, संघ का नाम हो और इसके लिए हमें एक जुट होकर काम करना है। हमें साथ मिलकर परिषद को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है।

श्री जैन श्वेताम्बर तैरापंथी सभा राजराजेश्वरीनगर की साधारण सभा आयोजित

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

श्री जैन श्वेताम्बर तैरापंथी सभा, राजराजेश्वरीनगर, बेंगलूरु की सप्तम साधारण सभा अध्यक्ष राकेश छाजेड़ की अध्यक्षता में रविवार को प्रातः 11 बजे से तैरापंथ भवन, राजराजेश्वरी नगर में आयोजित की गई। नमस्कार महामंत्र के सामूहिक स्मरण से बैठक की शुरुआत हुई एवं संघ गीत की प्रस्तुति संगायक मनीष पगारिया ने किया। उपरांत श्रावक निष्ठा पत्र का वाचन पूर्व अध्यक्ष कमल दुगड़ ने किया। मंत्री गुलाब बाँठिया ने गत वर्ष के मिनट्स का वाचन किया, जिसे सहर्ष स्वीकृत किया गया। अध्यक्ष राकेश छाजेड़ ने सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया। आचार्य ने गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए चातुर्मास संबंधित सभी जानकारीयों प्रदान की तथा सभी



का पूर्ण जागरूकता से सेवा दर्शन हेतु आह्वान किया। क्षेत्र के सभी अनुदानदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज डागा ने चातुर्मास काल में हर संभव सहयोग हेतु आश्वासन दिया। पूर्व अध्यक्ष कमलसिंह दुगड़, तैयुप अध्यक्ष बिकास छाजेड़, महिला मंडल अध्यक्ष सुमन पटवारी, विकास दुगड़ एवं

अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मंत्री गुलाब ने वर्ष भर का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसे सभा द्वारा पारित किया गया। आय-व्यय का ब्यौरा कोषाध्यक्ष देवेन्द्र नाहट द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिसे सदन द्वारा ओम अहंम् की ध्वनि से पारित किया गया। अध्यक्ष ने चौमासे में भवन में चौका सेवा शुरू करने एवं

गुरुदर्शन हेतु अहमदाबाद संघ लेकर जाने संबंधित सूचनाएं प्रदान की। ज्ञानशाला संयोजिका प्रिया छाजेड़ (राजराजेश्वरी नगर) तथा पूनम दक (केंगेरी) ने ज्ञानशाला की रिपोर्ट प्रस्तुत की। सीमा जैन ने जैन विद्या की तथा विकास दुगड़ ने आगम मंथन प्रतियोगिता की रिपोर्ट प्रस्तुत की। 15 वर्षों से ज्ञानशाला में सेवा देने हेतु प्रिया छाजेड़ को संयोजिका के रूप में सेवा देने हेतु सम्मानित किया गया। नीतु बाफना को ज्ञानशाला की संयोजिका नियुक्त किया गया।

तेममं की नवमनोनीत अध्यक्ष मंजू बोथरा को सम्मानित किया गया। सभा की उपाध्यक्ष सरोज आर बैद को जैन स्कालर बनने पर सम्मानित किया गया। संचालन मंत्री गुलाब बाँठिया ने एवं सहमंत्री राजेश भंसाली ने आभार व्यक्त किया।

रक्तदान महोत्सव परववाड़ा के अंतर्गत रक्तदान शिविरों का आयोजन

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

मायुम बेंगलूरु ने राष्ट्रीय प्रकल्प - रक्तदान महोत्सव परववाड़ा के अंतर्गत रविवार को शहर के तीन अलग-अलग स्थानों सव्व डिवीनिटी, सोभा ऐरिना और प्रेस्टीज जिंदल सिटी में एक साथ तीन सफल रक्तदान शिविरों का आयोजन किया। मा.यु.म के सदस्यों ने पूरे उत्साह व समर्पण के साथ भागीदारी निभाई, जिसके फलस्वरूप इन तीन शिविरों में कुल 165 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। शाखा अध्यक्ष गोपाल कुमार, सचिव सनी जैन एवं कोषाध्यक्ष विवेक खंडेलवाल ने इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी सदस्यों का



आभार व्यक्त किया। उन्होंने परियोजना संयोजक शुभम लोहिया को तीनों शिविरों के बीच समन्वय के लिए विशेष रूप से बधाई दी तथा शिविर प्रबंधकों वरुण अग्रवाल, विशाल धानुका, विनोद गर्ग, वैभव खंडेलवाल एवं एकता खंडेलवाल के प्रति भी आभार प्रकट किया। इसके साथ ही

निवर्तमान अध्यक्ष स्नेहकुमार जाजू, उपाध्यक्ष कन्हैया अग्रवाल एवं गौरव शर्मा, वरिष्ठ सदस्य पंकज जालान, पवन राजलीवाल एवं सुशील सैनी, साथ ही मनीष अग्रवाल, प्रितेश बुरड आदि अन्य सदस्यों ने भी अपनी सक्रिय उपस्थिति एवं योगदान से इस आयोजन को सफल बनाया।

डीआरएम ने माल दुलाई ग्राहकों के साथ एक इंटरैक्टिव बैठक आयोजित की

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

दक्षिण पश्चिम रेलवे के बेंगलूरु डिवीजन ने माल दुलाई सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से, उनकी प्रतिक्रिया सुनने और परिचालन चुनौतियों को समझने के लिए माल दुलाई ग्राहकों के साथ एक इंटरैक्टिव बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) आशुतोष कुमार सिंह ने की। उन्होंने माल दुलाई ग्राहकों को एक भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स पार्टनर के रूप में भारतीय रेलवे में उनके निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए धन्यवाद दिया।

उन्होंने बेहतर नीतियों को आकार देने, संचालन में सुधार और अभिनव माल दुलाई समाधान बनाने में हितधारकों की



प्रतिक्रिया के महत्व पर भी जोर दिया। बैठक के दौरान आशुतोष कुमार सिंह ने माल दुलाई संचालन में डिवीजन के लिए अब तक की डिवीजन के लिए अब तक का वित्तीय वर्ष 2024-25 में, डिवीजन ने माल राजस्व में 327.74 करोड़ कमाए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अकेले मई 2025 तक, इसने पहले ही 50.82 करोड़ कमा

लिया था। 16 जून 2025 को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई, जब डिवीजन ने एक ही दिन में रिकॉर्ड 513 बैगन लोड किए- जो डिवीजन के लिए अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। देवरापल्ली गुड्स शेड में कंटेनर हैंडलिंग 2 से बढ़कर 13 रैक प्रति माह हो गई है और इससे 0.57 करोड़ की कमाई हुई है। कंटेनर ऑपरेटों की सहायता के लिए देवगोथी को एक विशेष कंटेनर रेल टर्मिनल

घोषित किया गया है। इस वर्ष पेट्रोलियम तेल और स्नेहक (पीओएल) की लोडिंग में भी 102 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे 8.68 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। सेट्टीहल्ली गुड्स शेड को बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ अपग्रेड किया गया है, जिसमें कंक्रीट सर्कुलेंटिंग एरिया, चेक रेल और स्टैकिंग जोन शामिल हैं। ऑटोमोबाइल ले जाने वाली पहली एनएमजी रैक 21 मई 2025 को सेट्टीहल्ली से भेजी गई। अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक मोहनपुरिया ने आधुनिकीकरण परियोजनाओं पर अपडेट साझा किए। निदावंदा, पेनुकोंडा और क्यासंद्रा में माल शेडों में बड़े उन्नयन किए जा रहे हैं, साथ ही धर्मपुरी के लिए भी

प्रस्तावों की योजना बनाई गई है। बिदादी, देवरापल्ली, होसुर और हीलालिंगे में सीजीएसआर कमरे, व्यापारिक क्षेत्र और श्रमिक शौचालय वाली नई इमारतें बनाई जाएंगी। संचालन और बैगन टर्नआउट समय में सुधार के लिए व्हाइटफील्ड सैटेलाइट गुड्स टर्मिनल, डोड्डबल्लपुर और होसुर में भी उन्नयन हो रहा है। बैठक में टीसीआई लॉजिस्टिक्स, अदानी साइडिस, कॉनकार, आईवीसी लॉजिस्टिक्स और अन्य ने भाग लिया। उन्होंने अपनी चिंताओं और सुझावों को साझा किया। रेलवे अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा।

जेबीएन वी कनेक्ट रेफरल समूह की बैठक आयोजित

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

जेबीएन वी कनेक्ट द्वारा चौथी कार्यकाल बैठक का आयोजन जेआईटीओ बेंगलूरु नॉर्थ कार्यालय में सफलता पूर्वक किया गया। इस बैठक में जेएलडब्ल्यू कोषाध्यक्ष एवं जे.बी.एन कन्वीनर तनुजा मेहता तथा संयुक्त सचिव सुमन रांका की गरिमामयी उपस्थिति रही। बैठक की मुख्य वक्ता शुभम मेडिकल्स और जनरल स्टोर्स की सस्थापक लीला पितलिया रहीं,

जिन्होंने वन जे.बी.एन ऐप की जानकारी प्रस्तुत की। यह ऑन-इन-वन डिजिटल प्लेटफॉर्म जे.बी.एन समुदाय के भीतर नेटवर्किंग, रेफरल और व्यवसायिक विकास को सरल और सशक्त बनाने हेतु डिजाइन किया गया है। यह ऐप सदस्यों को व्यवसाय प्रदान करने, उसे ट्रैक करने, विभिन्न अध्यायों से जुड़ने तथा सामूहिक विकास में भागीदारी हेतु सक्षम बनाता है। बैठक में दो नए सदस्यों



का स्वागत भी किया गया। साथ ही, अंजना द्वारा सोक्षयल के लाभों पर एक शैक्षणिक स्टांट प्रस्तुत किया गया, जिससे सदस्यों को डिजिटल दुनिया की नई संभावना-1ओं की जानकारी मिली। कार्यक्रम का सफल संचालन रेफरल टीम द्वारा किया गया, जिसमें रेफरल हेड मीना जैन, रेफरल लीड लीला पितलिया तथा रेफरल सचिव सीए सुखदेवी जैन ने अपनी-अपनी भूमिका का कुशलतापूर्वक निर्वहन

किया। बैठक के दौरान सभी उपस्थित सदस्यों को अपनी 30-सेकंड की व्यवसायिक पिच प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया, जिससे सभी को एक-दूसरे के व्यवसाय को जानने और समझने का अनूठा मंच मिला। इस सत्र को और रोचक बनाते हुए तीन विशेष डोर प्राइज प्रदान किए गए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ 30 सेकंड की पिच के लिए दीपिका जैन, सबसे अधिक रेफरल

देने के लिए सुशीला श्रीश्रीमाल, तथा सबसे अधिक व्यवसाय देने के लिए निकिता जैन को सम्मानित किया गया। बैठक का समापन राष्ट्रागन के साथ किया गया। तत्पश्चात, सभी सदस्यों के लिए खुली नेटवर्किंग का अवसर प्रदान किया गया, जिसमें आपसी सहयोग एवं समूह के भीतर उपयोगी व्यवसायिक संबंधों को और सुदृढ़ करने की भावना अभिव्यक्त की गई।



अधिकारियों को श्रेय दिया जा रहा, विधायकों की अनदेखी की जा रही: विधायक राजू कागे

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

कागवाड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजू कागे ने एक बार फिर दोहराया कि अधिकारियों को श्रेय दिया जा रहा है। विधायकों की अनदेखी की जा रही है, सीएम, डीसीएम और मंत्रियों से अपील करने पर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं किस उद्देश्य से विधायक रहूँ, मैंने इस्तीफा देने का सोच लिया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र एनापुर टाउन पंचायत में सीसी रोड की गुडली पूजा में गए थे। वहां एक और सड़क मंजूर हुए एक साल हो गया है। कोई काम नहीं हुआ। जब उन्होंने ठेकेदार से पूछा तो उसने कहा कि पैसे नहीं हैं। मुख्यमंत्री के 25 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान में से सड़क निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपये तय किए गए। वहां भी अधिकारियों ने

विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि वे जेली रोड के लिए पैसे नहीं देंगे, लेकिन मटलिंग अस्पताल बनाया जाना चाहिए। नियम कहता है कि विधायकों द्वारा प्रस्तावित सामुदायिक घरों को बिना किसी शर्त के मंजूर किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इसका आदेश भी दिया है। 1 अप्रैल 2024 को ग्रामीण क्षेत्रों में 13 करोड़ रुपये की लागत से 72 सामुदायिक भवन बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया था। अभी तक इसके लिए कोई कार्य काई नहीं दिया गया है। उन्होंने जोरदार सवाल किया कि क्या हमारे विधायक का कार्यकाल समाप्त होने के बाद कार्य आदेश दिया जाएगा। बसवेश्वर एल्टा सिंचाई को 200 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। ठेकेदारों को 100 करोड़ रुपये जारी करने की जरूरत है। मैंने इस मुद्दे पर



मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से सौ बार पूछा है। कोई फायदा नहीं हुआ। अधिकारी वेतन पर कार्यालय में बैठते हैं। वे निर्वाचन क्षेत्रों में काम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ऐसी गंदी व्यवस्था में विधायक क्या करें? मैंने कहा था कि इस्तीफा देना बेहतर होगा। उस पर मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने जवाब दिया और कहा कि आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। हम 10 हजार लोगों के साथ आएं। चलो विधानसभा के सामने जाकर विरोध करते हैं। लेकिन लोगों को आने की जरूरत नहीं है, मैं सक्षम

हूँ। मैं समस्या का समाधान करूंगा और उन्हें आश्चर्य करूंगा। प्रशासनिक व्यवस्था को और तेज किया जाना चाहिए। विधायकों के साथ ही आम लोगों के काम भी तेजी से होने चाहिए। निजी स्कूलों में अग्निसुरक्षा उपकरण लगाने का सुझाव दिया गया है। एक-दो साल काम पूरा होने के बाद भी एनओसी नहीं दी जा रही है। राजू कागे ने मांग की कि ऐसा प्रशासन लागू किया जाना चाहिए, जहां कोई भी काम तीन से चार दिन में पूरा हो सके। जिला मंत्री विधायकों के साथ चपरासी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। आप कोई आवेदन देते हैं, तो उन्हें यह शिष्टाचार नहीं है कि वे उसे पढ़कर बताएं कि उस पर काम होगा या नहीं। वे किसी और से बात करते हैं, कागज हाथ में लेकर अपने घर चले जाते हैं। हमें उनके पीछे सर-सर कहकर जाना

चाहिए। क्या हमारा कोई सम्मान नहीं है? मैंने ग्राम पंचायत सदस्य, अध्यक्ष और विधायक के रूप में काम किया है। मैंने 8 चुनाव लड़े हैं और 5 जीते हैं। मेरे पिता देवेगौड़ा के करीबी मित्र थे। हम गांव में भिखारी को भी सम्मान देते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री से शिकायत करनी है तो खुलकर नहीं बोलना चाहिए। राजस्व विभाग के सचिव राजेंद्र कटारिया ने मेरा अपमान किया। मैंने विधानसभा में उनके खिलाफ शिकायत की थी। इस पर चर्चा भी हुई। 60 विधायकों ने मुख्यमंत्री को उक्त अधिकारी का तबादला करने के लिए पत्र लिखा था। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां सवाल उठता है कि अधिकारी मुखिया है या विधायक। क्या हमारा कोई मान-सम्मान नहीं है।

सत्ता से चिपके बिना इस्तीफा दें सीएम सिद्धरामैया: नारायणस्वामी

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाडी नारायणस्वामी ने कहा कि विपक्षी दल यह नहीं कह रहे हैं कि राज्य की कांग्रेस सरकार लूटपाट में लिप्त है, बल्कि कांग्रेस के विधायक ऐसा कह रहे हैं। लेकिन सरकार इसका जवाब नहीं दे पा रही है। यहां भाजपा कार्यालय जगन्नाथ भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम कह रहे हैं कि मैं फोन करके बात करूंगा, मैं मिल्गूआ और बात करूंगा। उन्होंने आपत्ति जताई कि मुख्यमंत्री ने ऐसा लचर जवाब देना शुरू कर दिया है।

अब लचर जवाब देना संभव नहीं है। कांग्रेसी भी हैं जो सीमा से अधिक भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकते। विधायक बी.आर. पाटिल के बाद गोपालकृष्ण ने भी कहा कि वे एक भी नाली या सड़क नहीं बना पा रहे हैं। उन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित



किया कि बेलूर गोपालकृष्ण ने कहा था कि मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। राजू कागे ने कहा कि उन्हें फंड नहीं मिल रहा है। एक-एक करके वे किसी न किसी तरह से सरकार के खिलाफ होने लगे हैं।

सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री को इस बात को समझते हुए तुरंत इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। आप अक्षम हैं, आप सिर्फ सत्ता से चिपके हुए हैं, आप इस बिगड़ी हुई व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते, इतने

लोग आपसे इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं, फिर भी आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। देवराज उर्स साढ़े सात साल तक मुख्यमंत्री रहे। आप उससे एक दिन भी आगे रहने की जिद कर रहे हैं। उन्होंने आलोचना की कि आप देवराज उर्स के समय की धूल के बराबर भी नहीं हैं। देवराज उर्स लगातार साढ़े सात साल तक मुख्यमंत्री रहे। जब आपको मौका मिला, तो आपने ठीक से काम नहीं किया, लोगों ने तिरस्कृत किया और अपने ही चामुंडेश्वरी निर्वाचन क्षेत्र में हार गए।

प्रेक्षाप्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जन्म जयंती पर भक्ति संध्या आयोजित

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

प्रेक्षाप्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की 106वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर तेरापंथ युवक परिषद, विजयनगर द्वारा भव्य भक्ति संध्या - यादें महाप्रज्ञ जी की का भव्य आयोजन एमसी लेआउट में रोशनलाल, दिनेश, राकेश पोखरणा के निवास स्थान प्रेमरोशन में किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ युगप्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी की सुशिष्या साध्वी संयमलता जी के पावन सान्निध्य एवं मंगलपाठ से हुआ। साध्वी ने अपने उद्बोधन में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के तप, ज्ञान और करुणा से भरे जीवन



पर प्रकाश डालते हुए उनकी प्रेरणाओं को आत्मसात करने का आह्वान किया।

साथ ही सम्पूर्ण पोखरणा परिवार की संघ भक्ति एवं गुरु भक्ति की प्रशंसा की। तेयुप अध्यक्ष कमलेश चोपड़ा ने सभी का स्वागत करते हुए गुरुदेव

महाप्रज्ञ जी के जन्मोत्सव पर अपनी भावनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन गायक ऋषि दुगड़ ने संगीतमय प्रस्तुति दी। साथ में विजय स्वर संगम टीम की प्रस्तुति रही। निधी चावत, नमन चवत, प्रकाश गाँधी, राकेश दूधोडिया, सम्पत

चावत, प्रेम भंसाली, महेंद्र टेबा, टी पी एफ राष्ट्रीय अध्यक्ष हिममत मांडोट, उपासक अरविन्द मांडोट ने अपने उद्गार व्यक्त किये। सैकड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में आयोजित इस भक्ति संध्या ने सभी को अध्यात्म और आत्मिक शांति से भर दिया।

उडुपी के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी

अहमदाबाद शहर साइबर शाखा पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

उडुपी/शुभ लाभ ब्यूरो।

उडुपी शहर के स्कूल को बम की धमकी वाला ईमेल भेजने वाले आरोपी को अहमदाबाद सिटी साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चेन्नई स्थित इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और आईटी फर्म में सीनियर कंसल्टेंट रेने जोशीलडा नामक महिला ने ये धमकी भरे ईमेल भेजने के लिए फर्जी ईमेल आईडी और फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल का इस्तेमाल किया।

उसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली, केरल, बिहार, तेलंगाना, पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा राज्यों में ये ईमेल भेजते हुए पकड़ा गया।



इन संगठनों में कुल 21 धमकी भरे ईमेल ट्रैक किए गए। आरोपी फर्जी ईमेल आईडी बनाकर, वीपीएन, वर्चुअल नंबर और डार्क वेब टूल्स का इस्तेमाल करके बम की धमकी वाले ईमेल भेजकर उड़ाने और दहशत पैदा कर रही थी। जिनेवा लिबरल स्कूल,

सरखेज में प्राप्त एक धमकी भरे ईमेल के संबंध में विष्णुभाई चमनभाई खाबड़िया द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के जवाब में, साइबर क्राइम ब्रांच की टीमों जांच में जुटी।

साइबर अपराध शाखा ने मानवीय खुफिया और साइबर

उपकरणों सहित गहन तकनीकी विश्लेषण किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें चेन्नई, तमिलनाडु में रहने वाली आरोपी रेने जोशीलडा तक पहुंचाया गया। ठोस सबूत इकठ्ठा करने के बाद, एक टीम को चेन्नई भेजा गया, जहाँ उन्होंने आरोपी को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए, उडुपी एसपी हरिराम शंकर ने कहा हम अहमदाबाद पुलिस को जांच के लिए आरोपी को हमें सौंपने के लिए पत्र लिखेंगे। अहमदाबाद पुलिस द्वारा जांच पूरी होने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि वह हमें सौंप दी जाएगी।

तीन भव्य रथों के साथ पहली बार निकाली जाएगी रथ यात्रा



बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

शहर में शुक्रवार को श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, माँ सुभद्रा और आयुध सुदर्शन के तीन भव्य रथों के साथ पहली बार रथ यात्रा निकाली जाएगी, जो बिक्रनहल्ली मेन रोड, बिक्रनहल्ली, सरजापुरा अर्जीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के पास स्थित है। यह महत्वपूर्ण अवसर शहर की एकता और समावेशिता की भावना का जश्र मनाता है।

बिक्रनहल्ली, सरजापुरा में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर सांप्रदायिक सद्भाव और समर्पण का उदाहरण है। मंदिर की यात्रा 2022 में शुरू हुई थी, जब स्थानीय कन्नड़ और अन्य समुदायों के साथ ओडिया भक्तों ने शहर के 2 लाख ओडिया निवासियों के लिए एक पवित्र स्थान की कल्पना की थी। चूंकि मंदिर अपनी पहली रथ यात्रा मनाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए समिति ने पुरी के प्रतिष्ठित उत्सव

के आकर्षक माहौल को फिर से बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है।

मंदिर समिति ने बड़ी भीड़ को समायोजित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं, जिसमें पुलिस की अनुमति प्राप्त करना और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करना शामिल है। मंदिर सद्भाव का प्रतीक बन गया है, जो ओडिया, कन्नड़, बंगाली और अन्य समुदायों के बीच की खाई को पाट रहा है।

सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों के खिलाफ चेतावनी

दोषी पाए जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा : पुलिस आयुक्त

मेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार रेड्डी ने हाल की घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि सुहास शेटी और अशरफ हत्या मामलों की जांच वैज्ञानिक तरीकों और सत्यापित साक्ष्यों का उपयोग करके की जा रही है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो। आयुक्त ने कहा सोशल मीडिया पर व्यापक अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसमें लोग सुझाव दे रहे हैं कि कैसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए या किसे रिहा किया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने दावा किया है कि सुहास शेटी और अशरफ



मामलों में दो महिलाएं और कुछ खास लोग शामिल थे। जांच प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा सुहास शेटी मामले को एनआईए को सौंपे जाने से पहले, हमारी टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों का उपयोग करके हर संभव कोण की गहन जांच की। सुहास शेटी और अशरफ दोनों मामलों में, हमने कुडुपु घटनास्थल पर मौजूद सभी 126 व्यक्तियों की पहचान की है और उन्हें पूछताछ के लिए

बुलाया है। सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों पर कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, रेड्डी ने कहा हां, संबंधित व्यक्ति घटनास्थल पर मौजूद था। हालांकि, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने अशरफ को उकसाया या उस पर हमला किया। सोशल मीडिया पर जो कुछ भी प्रसारित किया जा रहा है, उसके अलावा इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई गवाह सामने नहीं आया है। उन्होंने लोगों

से जांच में सहायता के लिए विश्वसनीय जानकारी देने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा हमारे कार्यालय और जांच अधिकारी अगले दो दिनों में उपलब्ध रहेंगे। वैध सबूतों के साथ कोई भी व्यक्ति आगे आ सकता है और हम उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। रेड्डी ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। हम हर नागरिक की सुरक्षा और भलाई के लिए जिम्मेदार हैं। अगर कोई मुद्दा उठता है, तो हम न्याय सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आगे चेतावनी दी कि अभद्र भाषा और नफरत फैलाने वाली पोस्ट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा किसी को भी नफरत फैलाने

वाली भाषा या भड़काऊ सामग्री फैलाने की स्वतंत्रता नहीं है। चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो, ऐसे कृत्यों में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नफरत को बढ़ावा देने का अधिकार नहीं देती है। कानून अपना काम करेगा और दोषी पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सांप्रदायिक मामलों को संभालने के लिए कानूनी अधिकारी नियुक्त किए गए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, राज्य सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में मेंगलूरु शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्राधिकार से सांप्रदायिक-संबंधित मामलों का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए चार कानूनी अधिकारियों की नियुक्ति की है।

स्वास्थ्य विभाग ने घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करने का शुरु किया अभियान

मेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

दक्षिण कन्नड़ में लगातार हो रही मानसूनी बारिश के कारण, मेंगलूरु सिटी कॉर्पोरेशन (एमसीसी) की सीमा में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके कारण जिला स्वास्थ्य विभाग को तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी है। अधिकारियों ने अब निगरानी बढ़ा दी है और बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए घर-घर जाकर जागरूकता और रोकथाम अभियान शुरू किया है। मानसून की गति बढ़ने के साथ डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। इस साल जनवरी से अब तक दक्षिण कन्नड़ जिले में डेंगू के 70 मामले दर्ज किए गए हैं। मेंगलूरु शहरी

और ग्रामीण क्षेत्र क्रमशः 15 और 16 मामलों के साथ सूची में सबसे ऊपर हैं। संक्रमण की रिपोर्ट करने वाले अन्य तालुकों में बेल्टांगडी (19 मामले), बंटवाल (10), कडाबा (5), मुल्की (3) और सुलिया (2) शामिल हैं। उल्लेखनीय रूप से, पुनूर में अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। मासिक मामलों के रद्धान चिंताजनक रूप से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। जनवरी में केवल 5 मामले दर्ज किए गए, इसके बाद फरवरी में 4, मार्च में 7 और अप्रैल में 6 मामले दर्ज किए गए। हालांकि, मई में चक्रवात के कारण हुई बारिश के बाद, संख्या बढ़कर 22 हो गई और जून



में अब तक 26 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि पिछले साल जून के अंत तक दर्ज किए गए 184 मामलों की तुलना में यह कम है, लेकिन इस साल लगातार हो रही वृद्धि ने

चिंता पैदा कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने एमसीसी की सीमा के भीतर चार पीएचसी (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) क्षेत्रों को डेंगू हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना है, जिसमें बिजई, लोडोहिल, शक्तिनगर और कसबा बेंगे शामिल हैं। इन क्षेत्रों पर अब विशेष निगरानी रखी जा रही है, जहां आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य निरीक्षक, सामुदायिक अधिकारी और स्थानीय स्वास्थ्य कर्मचारी रोजाना घर-घर जाकर जांच कर रहे हैं। इसके अलावा, 25 वेनलॉक पैरामेडिकल छात्रों को 100-दिवसीय डेंगू रोकथाम अभियान पर तैनात किया गया है, जो घरों में जाकर जागरूकता फैला रहे हैं

और मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करने में मदद कर रहे हैं। जिले के ग्रामीण इलाकों में रबर और सुपारी के बागान छिपे हुए प्रजनन हॉटस्पॉट के रूप में उभरे हैं। हाल ही में किए गए निरीक्षणों में रबर टैपिंग कप और गिरी हुई सुपारी की चादरों में पानी जमा होने का पता चला, जो मच्छरों के लार्वा के विकास के लिए आदर्श है। जिला स्वास्थ्य कार्यालय ने सभी ग्राम पंचायतों को परिपत्र भेजा है, जिसमें उन्हें लार्वा स्रोत में कमी लाने और मच्छरों के आवासों को खत्म करने के लिए ग्राम-स्तरीय निरीक्षण का समर्थन करने का निर्देश दिया गया है। डेंगू एडीज एजिप्टी मच्छर द्वारा फैलता है,

जो दिन के उजाले के दौरान सक्रिय रहता है। यह अपने पैरों पर अलग-अलग काले और सफेद धारियों से आसानी से पहचाना जा सकता है। जिससे इसे टाइगर मच्छर उपनाम मिला है। डेंगू के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं है। डॉक्टर लक्षणों का इलाज करते हैं और जटिलताओं की निगरानी करते हैं। जिला वेक्टर-जनित रोग नियंत्रण अधिकारी डॉ. जैसिंथा डिसूजा ने चेतावनी देते हुए कहा पर्याप्त आराम और तरल पदार्थ का सेवन महत्वपूर्ण है। यदि शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज किया जाता है, तो डेंगू जानलेवा हो सकता है।

जो दिन के उजाले के दौरान सक्रिय रहता है। यह अपने पैरों पर अलग-अलग काले और सफेद धारियों से आसानी से पहचाना जा सकता है। जिससे इसे टाइगर मच्छर उपनाम मिला है। डेंगू के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं है। डॉक्टर लक्षणों का इलाज करते हैं और जटिलताओं की निगरानी करते हैं। जिला वेक्टर-जनित रोग नियंत्रण अधिकारी डॉ. जैसिंथा डिसूजा ने चेतावनी देते हुए कहा पर्याप्त आराम और तरल पदार्थ का सेवन महत्वपूर्ण है। यदि शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज किया जाता है, तो डेंगू जानलेवा हो सकता है।

विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मध्य क्षेत्रीय परिषद की भूमिका अहम: अमित शाह

लखनऊ, 24 जून (एजेंसियां)। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने में मध्य क्षेत्रीय परिषद के राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

श्री शाह ने यहां मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुये कहा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद ही एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय परिषद है जहां दो सदस्य राज्यों के बीच किसी प्रकार की कोई समस्या या विवाद नहीं है और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उतराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भाग



लिया। बैठक में सदस्य राज्यों के वरिष्ठ मंत्री, केन्द्रीय गृह सचिव, अंतर-राज्य परिषद सचिवालय के सचिव, सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव और राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जहाँ 2004-14 तक जोनल काँसिल के सिर्फ

11 मीटिंग्स और स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ़ जोनल काँसिल्स के सिर्फ 14 मीटिंग्स हुए थे, वहीं 2014-25 में जोनल काउंसिल के 28 मीटिंग्स और स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ़ जोनल काँसिल्स के 33 मीटिंग्स हुए हैं, जो कि कुल 2 गुना वृद्धि है। साथ ही, उन्होंने यह भी स्पष्ट

किया कि अब तक इन बैठकों में 1287 मुद्दों का निराकरण किया गया है, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक भी है और उत्साह बढ़ाने वाला भी है। बैठक में गृह मंत्री ने सदस्य राज्यों की ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने और इसके लिए नियम बनाने को भी कहा। उन्होंने कहा

कि पंचायतों की आय बढ़ने से ही भारत की त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक पंचायती राज व्यवस्था और अधिक कारगर होगी।

बैठक में राष्ट्रीय महत्व के व्यापक विषयों सहित कुल 19 मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों की त्वरित जांच और इनके शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों का कार्यान्वयन, प्रत्येक गांव के नियत दायरे में ब्रिक-एंड-मोटरा बैकिंग सुविधा और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का कार्यान्वयन जैसे विभिन्न मुद्दे शामिल रहे। बैठक में गृह मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय परिषद के सभी राज्य बच्चों में कुपोषण दूर करने, ड्रॉप-आउट रेश्यो को जीरो करने और सहकारिता को सुदृढ़ बनाना सुनिश्चित करें।

ईपीएफओ ने ऑटो सेटलमेंट की सीमा पांच लाख की

नई दिल्ली, 24 जून (एजेंसियां)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने अंशधारकों के लिए भविष्य निधि जमा से 'ऑटो सेटलमेंट' के माध्यम से अग्रिम राशि निकालने की सीमा एक लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दी है।

ईपीएफओ के सूत्रों ने मंगलवार को यहां बताया कि कोविड काल के दौरान एक लाख रुपए तक के अग्रिम दावे के लिए ऑटो सेटलमेंट की सुविधा शुरू की गई थी जिसे अब पांच लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। इससे लाखों अंशधारकों को लाभ होगा। ईपीएफओ ने सबसे पहले कोविड-19 महामारी के दौरान सदस्यों के लिए वित्तीय सहायता के लिए यह सुविधा आरंभ की थी। बाद में इसे बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास जैसे आवश्यकता के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल में ईपीएफओ ने



अपनी सेवाओं को तेज़, पारदर्शी और जन अनुकूल बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। इनमें अपने ग्राहक को जानो, त्रुटि सुधार की प्रक्रिया को सरल बनाना आदि शामिल है। इसके अलावा अंशधारक को अपने प्रोफाइल सुधार के लिए नियोजता और ईपीएफओ पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सूत्रों अनुसार यह प्रक्रिया बिना किसी मानव संलिप्तता के तेज़ी और पारदर्शिता के साथ दावा निपटाती है।

वित्त वर्ष 2024-25 में ईपीएफओ ने ऑटो सेटलमेंट के जरिए रिकॉर्ड 2.34 करोड़ अग्रिम

दावे निपटारे हैं जो कि पिछले वर्ष 2023-24 के 89.52 लाख दावों की तुलना में 161 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2023-24 में जहां 31 प्रतिशत अग्रिम दावे ऑटो सेटलमेंट से निपटारे गये थे। वित्त वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 59 प्रतिशत हो गया।

आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के शुरुआती ढाई महीनों में ही ईपीएफओ ने 76.52 लाख दावे ऑटो सेटलमेंट से निपटारे हैं, जो अब तक के सभी अग्रिम दावे का 70 प्रतिशत हैं।

सीडीएस को तीनों सेनाओं को संयुक्त आदेश देने का अधिकार मिला

नई दिल्ली, 24 जून (एजेंसियां)। सरकार ने युद्ध और विभिन्न अभियानों के समय तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने तथा उनकी क्षमताओं का अधिकतम इस्तेमाल करने के उद्देश्य से प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) को तीनों सेनाओं को संयुक्त आदेश जारी करने का अधिकार दिया है।

रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और कार्यक्षेत्रों में बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सीडीएस को तीनों सेनाओं के लिए संयुक्त निर्देश और संयुक्त आदेश जारी करने के लिए अधिकृत कर दिया है। इससे पहले तीनों के प्रमुख युद्ध या आक्रमित

स्थिति तथा अभियानों में अलग-अलग आदेश जारी करते थे। 'संयुक्त निर्देशों' एवं 'संयुक्त आदेशों' के अनुमोदन और प्रकाशन के संदर्भ में पहला संयुक्त आदेश आज ही जारी किया गया है। यह प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, कई स्तर पर आदेशों की पुनरावृत्ति को समाप्त करने और अंतर-सैन्य सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देता है। यह पहल तीनों सेनाओं में बेहतर पारदर्शिता, समन्वय और प्रशासनिक दक्षता की नींव रखती है। यह एकजुटता एवं एकीकरण के एक नए युग की शुरुआत की भी प्रतीक है, जो राष्ट्र की सेवा में कार्यरत सशस्त्र बलों के सामंजस्य को और सशक्त बनाती है।

मूंग और उड़द की मूल्य समर्थन योजना पर होगी खरीद

नई दिल्ली, 24 जून (एजेंसियां)। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए मूंग और उड़द की खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत करने की घोषणा की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को यहां एक बैठक में मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द तथा उत्तर प्रदेश में उड़द को मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस) के अंतर्गत खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। उन्होंने खरीद से संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ चर्चा की और नेफेड, एन.सी.सी.एफ. और राज्य के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के लिए राज्य



सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर मंत्रालय के विचार करने तथा केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार और अन्यो के साथ बैठक के उपरांत पी.एस.एस. के अंतर्गत राज्य में ग्रीष्मकालीन मूंग तथा ग्रीष्मकालीन उड़द खरीद करने की मंजूरी प्रदान की गई है। उत्तरप्रदेश में पी.एस.एस. के अंतर्गत राज्य में ग्रीष्मकालीन उड़द खरीद करने की मंजूरी प्रदान की गई है।

श्री चौहान ने कहा कि मूंग और उड़द की खरीद के फैसले से केंद्र सरकार को वित्तीय भार वहन करना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद सरकार किसान हित में किसानों तक लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खरीद का सही तरीका सुनिश्चित करना आवश्यक है। किसानों से सीधे खरीद से ही बिचौलियों की सक्रियता कम होगी और लाभ

सही मायनों में किसान तक पहुंच पाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि आधुनिकतम और कारगर प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के साथ किसानों के पंजीकरण की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर खरीद केंद्रों की संख्या में भी इजाफा करना चाहिए और उचित तथा पारदर्शी व्यवस्था के साथ खरीद सुनिश्चित होनी चाहिए। श्री चौहान ने भंडारण में अनियमितताओं की शिकायत को लेकर भी चिंता व्यक्त की और अधिकारियों और कृषि मंत्रियों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने के प्रयास करने को कहा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में हर्ससंभव काम करेगी।

कांग्रेस ने जताई अमेरिकी यात्रा सलाह पर कड़ी आपत्ति



नई दिल्ली, 24 जून (एजेंसियां)। कांग्रेस ने भारत के संबंध में अमेरिकी यात्रा परामर्श को लेकर केंद्र सरकार की चुप्पी पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है कि इस मामले को अमेरिका के समक्ष उठाना चाहिए।

कांग्रेस की प्रवक्ता और डिजिटल एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत मंगलवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अमेरिका ने भारत में यात्रा करने वाले अमेरिकी नागरिकों के लिए एक परामर्श जारी किया है जो बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

अमेरिका ने पिछले सप्ताह अपने नागरिकों को एक परामर्श जारी किया है जिसमें भारत को भी लेकर सावधानी बरतने को कहा गया है।

यात्रा की दौरान महिलाओं को अकेले नहीं रहने को भी कहा गया है। सलाह में अमेरिकी सरकार के कर्मचारियों से भारत

की यात्रा करने से पहले पूर्व अनुमति लेने के कहा गया है। सुश्री श्रीनेत ने इस घटनाक्रम पर केंद्र सरकार की चुप्पी पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि इसके देश के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले को अमेरिकी सरकार के समक्ष उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसे देश के लिए ऐसी कोई सलाह नहीं दी गयी है जो आतंकवादियों को संरक्षण देता है लेकिन दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के लिए ऐसी सलाह है। उन्होंने कहा कि यह मोदी सरकार की एक और कूटनीतिक विफलता है।

उन्होंने कहा कि इस परामर्श से न केवल वैश्विक मंच पर भारत की छवि और प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बल्कि देश में पर्यटन और निवेश को भी नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि यह विदेश नीति की गंभीर विफलता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से देश के सामने मौजूद महिला सुरक्षा समेत कुछ गंभीर मुद्दों पर ध्यान देने जरूरत है।

1 जुलाई से ट्रेन का सफर होगा महंगा!

किराया बढ़ाने की तैयारी में भारतीय रेलवे

नई दिल्ली, 24 जून (एजेंसियां)। भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कई वर्षों में पहली बार यात्री ट्रेन के किराए में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर ली है। संशोधित दरें 1 जुलाई से लागू होंगी। रिपोर्ट के अनुसार, गैर-एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रति किलोमीटर 1 पैसे की दर से किराया बढ़ाना होगा। मंगलवार को रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि देशभर में रोजाना



करीब 13,000 गैर-एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में टिकट की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी होगी। एसी श्रेणी के यात्रियों के लिए किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर

की बढ़ोतरी होगी। रेलवे अधिकारी ने आश्वासन दिया कि नए किराया ढांचे से यात्रियों के बजट पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। उपनगरीय ट्रेन

के किराए और मासिक सीजन टिकट की कीमतें अपरिवर्तित रहेंगी, जिससे काम पर आने-जाने वाले दैनिक यात्रियों को राहत मिलेगी। इसके अलावा, साधारण

द्वितीय श्रेणी में 500 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए किराए में कोई वृद्धि नहीं होगी।

हालांकि, सामान्य द्वितीय श्रेणी में 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए, किराए में प्रति किलोमीटर केवल आधा पैसा ही बढ़ेगा। उदाहरण के लिए, 600 किलोमीटर की यात्रा में केवल 50 पैसे की वृद्धि होगी, जिसे बहुत मामूली माना जाता है।

इससे पहले जून 2025 में भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की थी। 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट

बुक करने के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। रेल मंत्रालय ने 10 जून 2025 को एक निर्देश जारी किया, जिसमें कहा गया कि इस उपाय का उद्देश्य तत्काल योजना का लाभ आम जनता तक पहुंचाना और एजेंटों द्वारा दुरुपयोग को रोकना है। भारतीय रेलवे की अधिसूचना के अनुसार, 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट केवल उन्हीं यात्रियों को उपलब्ध होंगे जिन्होंने आधार सत्यापन पूरा कर लिया है। बुकिंग केवल आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के माध्यम से की जा सकती है।

भ्रष्टाचार उजागर करने वाले पत्रकार को थाने में टॉर्चर

पटना, 24 जून (एजेंसियां)। बिहार में पुलिस तंत्र की कार्यशैली एक बार फिर कठघरे में है। मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र के फुलहर गांव निवासी पत्रकार हरि शम्भू की गिरफ्तारी और थाने में उनके साथ कथित अमानवीय व्यवहार के खिलाफ अब पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। पत्रकार ने कुछ सप्ताह पूर्व रिश्त लेते हुए थाना के एक अधिकारी का वीडियो सार्वजनिक किया था, जिसके बाद यह पूरा मामला सामने आया।

20 जून की रात करीब 8 बजे हरलाखी थानाध्यक्ष अनूप कुमार, अपर थानाध्यक्ष आदित्य कुमार समेत 20 पुलिसकर्मियों की टीम ने पत्रकार हरि शम्भू को उनके घर से बिना किसी पूर्व सूचना, प्राथमिकी या वारंट के हिरासत में ले लिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि इस

दौरान पुलिस ने पत्रकार की मां के साथ भी दुर्व्यवहार किया।

पत्रकार को करीब 22 घंटे तक थाने में रखा गया, जहां उनके साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त कर बंदूक की नोक पर जबरन उसका डेटा फॉर्मेट कराया, ताकि रिश्त से संबंधित डिजिटल सबूत मिटाए जा सकें।

थाने से रिहा होने के बाद पत्रकार की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें मधुबनी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान, सूजन और मानसिक तनाव की पुष्टि की गई है। घटना के बाद पुलिस महानिदेशक विनय कुमार को शिकायत सौंपी गई, जिसके आधार पर एएसआई प्रमोद कुमार और चौकीदार अजय कुमार को निलंबित कर दिया गया।

धन की कोई कमी नहीं है, नौकरशाही का लीक से हटकर न सोचना चिंता का विषय: गडकरी

पुणे (महाराष्ट्र): 24 जून (एजेंसियां)

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि परियोजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं है लेकिन नौकरशाही में लचीलेपन की कमी और लीक से हटकर न सोचना चिंता का विषय है।

गडकरी ने सोमवार को पुणे में एक कार्यक्रम में कहा कि पूर्व नौकरशाह विजय केलकर ने लचीला रुख अपनाया और वे अपवाद हैं।

इस समारोह में केलकर को पुण्यभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

उन्होंने कहा, “ हमारे पास धन की कमी नहीं है। मैं हमेशा एक लाख करोड़, 50,000 करोड़ या दो लाख करोड़ रुपये की



परियोजनाओं की बात करता हूं। आम तौर पर पत्रकार बड़ी घोषणाओं के मामले में राजनेताओं

पर भरोसा नहीं करते। मैं उनसे कहता हूं कि मैं जो कहता हूं उसे रिकॉर्ड करें और अगर काम पूरा

नहीं होता है तो 'ब्रेकिंग न्यूज' चलाएं।

मंत्री ने यह भी कहा कि चिंता धन की उपलब्धता की बजाय काम की धीमी गति को लेकर है। उन्होंने कहा, ग्रामीण इलाकों में जब भवेली चरने जाते हैं तो वे एक ही पंक्ति में चलते हैं। वे इतने अनुशासित होते हैं कि कभी भी क्रम नहीं तोड़ते। मुझे कभी-कभी नौकरशाही के बारे में भी यही महसूस होता है। यहां लीक से हटकर विचार अपनाना पूरी तरह मना है। हालांकि केलकर सर ने नीति-निर्माण में लचीलेपन को स्वीकार किया।

गडकरी ने कहा कि उन्होंने केलकर से उस समय मुलाकात की थी जब वह वित्त आयोग के चेयरमैन थे और उन्हें बताया था

कि 3.85 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 406 परियोजनाएं रुकी हुई हैं और बैंकों के सामने तीन लाख करोड़ रुपये की गैर-निष्पादित आस्तियां होने का खतरा है।

मंत्री ने कहा, उन्होंने मुझसे पूछा कि इसका कारण क्या है। मैंने उनसे कहा कि इसका एकमात्र कारण नौकरशाह है। हमने कुछ परियोजनाओं को समाप्त करके और कुछ में सुधार करके समस्या का समाधान किया।

परियोजनाएं फिर से शुरू हुईं और बैंकों को तीन लाख करोड़ रुपये की गैर-निष्पादित आस्तियों से बचाया गया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, केलकर ने हर विभाग में उत्कृष्ट कार्य किया, लेकिन वित्त सचिव के रूप

में उन्होंने जो नीतियां तैयार कीं, उनका भारत के भविष्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा।

गडकरी ने बताया कि 2009 में जब (भारत के पूर्व राष्ट्रपति) प्रणब मुखर्जी केंद्रीय वित्त मंत्री थे, तब केलकर कई चुनौतियों का सामना करते हुए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) पर आम सहमति बनाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा किया जाना चाहिए क्योंकि यह देश के हित में था।

इस अवसर पर केलकर ने कहा कि राजनेता ही सामाजिक और आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देते हैं।

उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वे ही असली नीति निर्माता हैं क्योंकि वे ही निर्णय लेते हैं।



बालू माफिया नेताओं की खुली दादागिरी भाजपा विधायक ने एसडीएम पर चलाया थप्पड़

बिना नंबर के ओवरलोड ट्रक सीज करने पर नेता बौखलाया

बांदा, 24 जून (एजेंसियां)।

बांदा में मौरंग (बालू) लंदे ओवरल-ोड ट्रक छुड़ाने पहुंचे भाजपा विधायक प्रकाश द्विवेदी ने एसडीएम अमित शुक्ला पर थप्पड़ जड़ दिया। विधायक ने पुलिस कर्मियों से भी धक्का-मुक्की और हाथा-पाई की। विधायक और उसके साथियों ने खुरहंड पुलिस चौकी पहुंचकर वहां खड़े कराए गए ट्रकों को छोड़ने के लिए हंगामा किया।

इस मामले में एसडीएम के वाहन चालक ने चार नामजद और 25-30 अज्ञात के खिलाफ 10 धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। हालांकि रिपोर्ट में विधायक का नाम शामिल नहीं है। विधायक ने पूरे प्रकरण से जिलाधिकारी को अवगत कराया है। गिरवां के खुरहंड स्टेशन के पास निर्माणाधीन शंकरजी के मंदिर के बाहर मौरंग उतार रहे दो ट्रकों को एसडीएम नरैनी अमित शुक्ला और सीओ नरैनी कृष्णकांत त्रिपाठी ने कागज न मिलने पर रविवार की रात करीब साढ़े 10 बजे सीज कर दिया। दोनों ट्रकों को



पुलिस चौकी खुरहंड में खड़ा करा दिया गया।

इसकी जानकारी सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी को हुई तो उन्होंने एसडीएम को फोन किया। फोन न उठाने पर रात करीब साढ़े 11 बजे तीन-चार गाड़ियों के काफिले के साथ एसडीएम की लोकेशन लेकर वह पैगंबरपुर-जरूर मार्ग पर पहुंच गए। वहां विधायक और उनके साथियों की एसडीएम अमित शुक्ला की तीखी झड़प हो गई। चर्चा है कि विधायक के साथियों ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिए।

इसके बाद विधायक काफिले के साथ खुरहंड पुलिस चौकी पहुंचे। वहां तैनात चौकी इंचार्ज यज्ञ नारायण भार्गव से पकड़े गए ट्रकों की चाबियां मांगीं। चौकी इंचार्ज ने एसडीएम द्वारा सीज करने का हवाला देकर चाबी देने से इंकार कर दिया। आरोप है कि विधायक ने चौकी इंचार्ज और सिपाहियों को फटकार लगाई। धक्का-मुक्की भी की।

घटनाक्रम के बाद एसडीएम अमित शुक्ला सोमवार को अपने आवास से बाहर नहीं निकले। उनके दोनों मोबाइल

भी बंद थे। मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। इस मामले में एसडीएम के ड्राइवर कामता प्रसाद मिश्रा ने गिरवां थाने में तहरीर दी। बताया कि एसडीएम नरैनी अमित शुक्ला के साथ अवैध खनन, ओवरलोडिंग की जांच कर रहे थे। खुरहंड रोड से ओवरलोड मौरंग भरे दो ट्रकों को सीज कर खुरहंड चौकी में खड़ा कराया था। रात करीब 11:45 बजे एसडीएम के साथ पैगंबरपुर-जरूर रोड पर मौजूद थे।

तभी छह गाड़ियों से इटरा खुरहंड निवासी ललित गुप्ता, आलोक सिंह, छोटकू द्विवेदी, बड़कू द्विवेदी 25-30 साथियों के साथ आए और एसडीएम की गाड़ी के सामने गाड़ियां लगाकर अभद्रता करते हुए गाड़ी को लाठी-डंडों से ठोक्ते पलटाने का प्रयास किया। उसने मना किया तो कालर पकड़कर जमीन पर पटक दिया, ड्राइवर के सिर पर जैक की रॉड मारी। तहरीर में ड्राइवर ने विधायक का नाम शामिल नहीं किया है।

सपा से निष्कासित बागी विधायक मनोज पांडेय जल्द देंगे इस्तीफा

लखनऊ, 24 जून (एजेंसियां)।

सपा से निष्कासित किए गए बागी विधायक मनोज पांडेय जल्द ही विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके लिए रणनीति पहले से ही तय है। भाजपा नेतृत्व से भी उन्हें आश्वासन मिल चुका है। उल्लेखनीय है कि समाजवादी पार्टी ने सोमवार को तीन विधायकों को पार्टी से निकाल दिया था। इनमें मनोज कुमार पांडेय शामिल हैं। पांडेय वर्तमान में रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक हैं।

दोबारा चुनाव जीतने की स्थिति में वे सरकार में अहम जिम्मेदारी पा सकते हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने या गैरहाजिर रहने वाले आठ विधायकों में से सिर्फ मनोज पांडेय ने ही अभी तक भाजपा की सदस्यता ली है। उन्होंने अपना सफर स्थानीय निकाय चुनाव से शुरू किया था। वे चार बार के विधायक हैं। वर्ष 2004-07 और 2012-17 की सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। सपा में भी उनके पास अहम जिम्मेदारियां थीं। वे सपा के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं। जिस समय उन्होंने बगावत करके राज्यसभा चुनाव में



भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया था, तब भी वे विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक थे।

पांडेय सपा के निष्कासन के बाद दल-बदल कानून से मुक्त हो गए हैं। उनके नजदीकी बताते हैं कि इसके बावजूद वे विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे, ताकि उपचुनाव में भाजपा से टिकट पाकर फिर से सदन में पहुंच सकें। बताते हैं कि इसके लिए उन्हें भाजपा नेतृत्व से आश्वासन भी मिल चुका है। भाजपा के अंदर उच्चस्तर पर बनी रणनीति के तहत ही इस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। यह इसलिए भी जरूरी

है कि मनोज पांडेय सपा के टिकट पर चुनाव जीते हैं और भाजपा नेतृत्व नहीं चाहता कि इस स्थिति में उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने से गलत संदेश जाए।

इससे पहले कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान के मामले में भी ऐसा ही किया गया था। वे 2022 में सपा के टिकट पर घोसी से विधायक चुने गए थे, इसलिए उन्होंने भी मंत्री बनाए जाने का आश्वासन मिलने पर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, उपचुनाव में वे हार गए। पार्टी ने उन्हें विधान परिषद भेजकर मंत्री बनाया।

ऑन ड्यूटी आर्मी लिखे ट्रक से तीन करोड़ का गांजा बरामद



मऊ, 24 जून (एजेंसियां)।

मऊ पुलिस एवं एसटीएफ की टीम ने तीन करोड़ का 12.50 किंटल गांजा बरामद किया है। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त टीम ने तालिमुदीन इंटर कॉलेज के पास एक ट्रक से 3.12 करोड़ रुपए कीमत का 12.50 किंटल गांजा पकड़ा।

एसटीएफ को सूचना मिली थी कि एक ट्रक को आर्मी के ट्रक का रूप देकर गांजा की तस्करी की जा रही है।

मऊ पुलिस के साथ मिलकर एसटीएफ ने तालीमुदीन इंटर कॉलेज के पास उस ट्रक को पकड़ लिया। पुलिस ने वाहन से सुल्तानपुर जनपद के बेथरा कादरी थाना के गंगपुर भुलिया निवासी

जनादन पांडेय को गिरफ्तार किया। तस्कर ने गांजे की खेप को छिपाने के लिए सेना के पदाधिकारी के नाम पर घरेलू सामान पर्वी चप्पा किया था।

इतना ही नहीं पुलिस को चकमा देने के लिए ट्रक में गांजा का स्टॉक रखने के बाद उसके ऊपर से घरेलू सामान रखा गया था। संयुक्त टीम की पूछताछ में गांजा तस्कर व ट्रक चालक ने बताया कि बलिया जनपद के सुखपुरा निवासी छोटू ने असम में अलबरा नामक एक व्यक्ति से गांजा ट्रक में लोड कराया और लखनऊ में मुलाकात होने की बात कही। बताया कि असम से लखनऊ गांजा पहुंचाने पर प्रति चक्र 70 हजार रुपए देने की बात की थी।

विकास पर खर्च में यूपी देश में नंबर वन

26 राज्यों के पूंजीगत व्यय में हिस्सेदारी 16 फीसदी से ज्यादा

लखनऊ, 24 जून (एजेंसियां)।

विकास और औद्योगिक गतिविधियों में खर्च के मामले में यूपी देश में नंबर वन है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के मुताबिक 26 राज्यों के पूंजीगत व्यय में यूपी की हिस्सेदारी 16 फीसदी से ज्यादा है। इसमें शराब और तंबाकू से राजस्व का योगदान लगभग 21 फीसदी है।

विकास और बुनियादी ढांचे में सबसे ज्यादा खर्च यूपी में हो रहा है। इसकी वजह तेज औद्योगिक विकास है। इस मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के मुताबिक, 26 राज्यों का पूंजीगत व्यय वित्तवर्ष 2024-25 में 8.7 खरब रुपए से बढ़कर वित्तवर्ष 2025-26 में 10.2 खरब रुपए हो जाएगा। इसमें केवल पांच राज्यों की हिस्सेदारी 50 फीसदी है। खास बात ये है कि इन पांच राज्यों में भी

अकेले यूपी का योगदान 16.3 फीसदी है, जो देश में किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा है।

ये इस बात का संकेत है कि बुनियादी विकास में खर्च करने के मामले में गुजरात दूसरे स्थान (9.4 फीसदी), महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर (8.3 प्रतिशत), मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर (8.1 प्रतिशत) और कर्नाटक पांचवें स्थान पर (6.7 प्रतिशत) है।

वित्त वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 16.9 प्रतिशत, महाराष्ट्र (10.9 प्रतिशत), गुजरात (8.1 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (7.5 प्रतिशत) और ओडिशा की 6.4 प्रतिशत थी। साफ है कि आने वाले वर्ष में भी इन्हीं पांच राज्यों में विकास की दौड़ में प्रतिस्पर्धा रहेगी।

रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान वित्त वर्ष में

26 राज्यों की कुल प्राप्ति 69.4 खरब रुपए का अनुमान है। ये धनराशि पिछले वित्त वर्ष से 10.6 प्रतिशत ज्यादा है। राज्यस्व प्राप्ति में 12.3 प्रतिशत की वृद्धि और पूंजीगत प्राप्ति में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान बैंक ने लगाया है।

इसमें भी एक बार फिर उत्तर प्रदेश के 13.3 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर बने रहने की उम्मीद है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र (11.3 प्रतिशत), और मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान 5.9 प्रतिशत के साथ काबिज हैं हैं। तमिलनाडु इस बार शीर्ष पांच में शामिल नहीं है।

बैंक आफ बड़ौदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी राज्य आंतरिक करों पर बहुत अधिक निर्भर रहेंगे और जीएसटी स्वयं के कर राजस्व का सबसे बड़ा

हिस्सा होगा। राज्यों को जीएसटी, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और स्टाम्प शुल्क सहित अन्य करों से 89 प्रतिशत आय का अनुमान है।

इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जीएसटी (44.2 प्रतिशत) का होगा। नागालैंड (67.3 प्रतिशत), दिल्ली (59.7 प्रतिशत) और बिहार (57.1 प्रतिशत) जीएसटी पर सबसे अधिक निर्भर हैं, जबकि मध्य प्रदेश (38.6 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (37.4 प्रतिशत) और अरुणाचल प्रदेश (19.7 प्रतिशत) की निर्भरता कम है। शराब और तंबाकू पर लगने वाला राज्य उत्पाद शुल्क का योगदान 13.9 फीसदी होने का अनुमान जताया गया है। इस श्रेणी में शीर्ष तीन राज्य सिक्किम (27.3 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (24.9 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (21.4 प्रतिशत) हैं।

अब आलू से बनेगा आटा, दुनियाभर में होगा निर्यात

आगरा, 24 जून (एजेंसियां)।

फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कहा कि अब आलू से आटा बनेगा। दुनियाभर में इसका निर्यात बढ़ाया जाएगा। सब्जियों का राजा अब विश्व पटल पर छाएगा। आलू का आटा बनेगा।

दुनियाभर में इसका निर्यात बढ़ेगा। यह संभव हो रहा है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई) के वैज्ञानिकों की मेहनत से। आलू का आटा बनाने के अलावा मोटे अनाज की ग्लूटेन रहित ब्रेड से लेकर जेम, जैली सहित एक दर्जन



उत्पादों में नवाचार हो रहा है।

रावी इवेंट्स, चैंबर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन और एमएसएमडी के सहयोग से आयोजित फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव 2025 के दूसरे दिन सोमवार को तकनीकी सत्रों का दौरा चला। केंद्रीय खाद्य

प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई) के वैज्ञानिकों ने फूड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। मैसूर से आई खाद्य वैज्ञानिक डॉ. विजयलक्ष्मी एस ने बताया कि उत्तर प्रदेश में एक दर्जन नवाचार पर काम शुरू किया है, जिसमें आलू का आटा खास

है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण के लिए तकनीकी जानकारीयां दीं। खाद्य वैज्ञानिक डॉ. खुशबू शर्मा ने बताया कि कैसे कम से कम प्रसंस्करण के माध्यम से खाद्य पदार्थों की प्राकृतिक संरचना, पोषण और स्वाद को बनाए रखा जाए।

उन्हें लंबी अवधि तक सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने मोटे अनाज पर आधारित रेडी-टू-कुक और रेडी-टू-ईट उत्पादों पर जोर दिया। डॉ. विजयलक्ष्मी ने बताया कि सीएफटीआरआई अब तक 300 से अधिक खाद्य प्रोसेसिंग तकनीकों का स्थानांतरण कर चुका है।

चौथे सत्र में फेडरेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय खाद्य पदार्थों की मांग पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ी है। 200 से अधिक देशों में भारतीय मसाले, सब्जियां आदि निर्यात हो रहा है। लेकिन, फिर भी निर्यात का ये प्रतिशत 2 प्रतिशत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि अफ्रीकी देश, यूरोप, साउथ एशिया के देशों में भारतीय खाद्य पदार्थों की बहुत मांग है। यदि खाद्य उद्यमी निर्यात को प्राथमिकता दें, तो विश्व की हर थाली में भारतीय भोजन की महक उठेगी।

राज्यसभा चुनाव में हुई सात क्रास वोटिंग, कार्रवाई सिर्फ तीन पर

लखनऊ, 24 जून (एजेंसियां)।

राज्यसभा चुनाव में सात क्रास वोटिंग हुई थी और एक विधायक गैरहाजिर रहे थे। लेकिन, कार्रवाई सिर्फ तीन बागी विधायकों पर क्यों की गई? इसको लेकर समाजवादी पार्टी में सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने केवल तीन विधायकों को ही पार्टी से क्यों निकाला? जबकि, राज्यसभा चुनाव में कुल सात विधायकों ने क्रास वोटिंग की थी और एक विधायक गैरहाजिर रही थीं। वहीं, बरेली के सपा विधायक शहजिल

इस्लाम का वोट रिजेक्ट होने पर भी सवाल उठे थे।

सपा नेतृत्व का कहना है कि निकाले गए तीन विधायक मनोज पांडेय, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह सपा के खिलाफ खुल कर अभियान चला रहे थे। ये भाजपा के पक्ष में खुले तौर पर सक्रिय थे। अन्य पांच विधायकों के मामले में बैसी स्थिति नहीं है। इनमें से कुछ तो अपने एकदम निजी हितों के चलते सत्ताधारी दल के करीब हैं। इन विधायकों के व्यवहार को सपा नेतृत्व ने भी अच्छा बताया है।

सपा के एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि जिन बागी विधायकों को निष्कासित नहीं किया गया है, उनमें से कुछ तो पार्टी नेतृत्व के साथ सम्पर्क में हैं। समय आने पर उनकी घर वापसी भी हो सकती है। सपा के मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि पार्टी ने काफी सोच-समझकर तीन बागी विधायकों को ही निष्कासित करने का फैसला किया है। इसकी सूचना विधानसभा अध्यक्ष को भेजे जाने के बाबत फिलहाल वे कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं है।

विलीन रियासतों के कालखंड के धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार होगा

लखनऊ, 24 जून (एजेंसियां)।

यूपी में विलीन हो चुकी रियासतों के कालखंड के धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके लिए धर्मार्थ कार्य विभाग ने नियमावली बनाई है। जिलों से प्रस्ताव मांगे हैं। इस कमेटी में पुरातत्व विशेषज्ञ व मंदिर आर्किटेक्ट भी शामिल होंगे। आजादी के बाद प्रदेश में स्वतंत्र रियासतें सरकार में विलीन हो गईं। उस समय सार्वजनिक प्रयोग में धार्मिक स्थल भी राज्य सरकार के अधीन हो गए थे। प्रदेश सरकार ने विलीन हुई रियासतों के धार्मिक स्थलों के रखरखाव, उनके संरक्षण व सुदृढ़ीकरण का निर्णय लिया है। इसके लिए धर्मार्थ कार्य विभाग ने विस्तृत नियमावली बनाई है। साथ ही जिलों से

इसके लिए प्रस्ताव मांगा है। धर्मार्थ कार्य विभाग ने कहा है कि योजना के तहत उन मंदिरों के जीर्णोद्धार को वरीयता दी जाएगी, जहां अधिक श्रद्धालु व पर्यटक आते हों। वे ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक व पौराणिक महत्व के हों। डीएम द्वारा जीर्णोद्धार की संस्तुति करने से पहले संबंधित मंदिर का स्थलीय निरीक्षण व सर्वे किया जाएगा। यह देखा जाएगा कि उसकी भूमि पर राज्य सरकार का स्वामित्व है। इसके लिए धर्मार्थ कार्य निदेशालय द्वारा तकनीकी समिति का गठन कर धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार संबंधित प्रस्तावों का परीक्षण किया जाएगा। इस समिति में पुरातत्वविद, मंदिर वास्तु विशेषज्ञ को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा।

लखनऊ, 24 जून (एजेंसियां)।

यूपी सरकार ने सामूहिक विवाह योजना में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए वर और वधू के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह के लिए सामूहिक विवाह योजना की निगरानी सख्त करने के निर्देश दिए हैं। कन्या के आधार सत्यापन में लापरवाही पर

अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके साथ ही विवाह स्थल पर वर-वधू दोनों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी, ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके। विवाह में दी जाने वाली उपहार सामग्री, जलपान और भोजन आदि के मानक तैयार कर उनका कड़ाई से पालन करवाया जाएगा।

एक ही स्थान पर 100 या उससे अधिक जोड़ों की शादियां



की स्थिति में संबंधित जिलाधिकारी स्वयं मौजूद रहेंगे। समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि योजना का लाभ पात्र परिवार आसानी से ले सकें। इसके लिए

कई स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं। योजना में लाभार्थियों को दिए जाने वाले उपहारों की गुणवत्ता और आपूर्ति में पारदर्शिता के लिए अब फर्मों के चयन की प्रक्रिया निदेशालय स्तर से की जाएगी, ताकि जिला स्तर पर किसी तरह की अनियमितता न हो।

समारोह में मंडलीय उपनिदेशकों और जिला समाज कल्याण अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। एक

जिले के अधिकारी दूसरे जिले में ऑब्जरवर के रूप में नामित कर भेजे जाएंगे। समारोह में किसी भी अनियमितता की स्थिति में ये अधिकारी सीधे निदेशालय या मंडलीय उपनिदेशक को रिपोर्ट करेंगे। योजना के प्रभारी उप निदेशक, समाज कल्याण आरपी सिंह ने बताया कि इस वर्ष लगभग एक लाख जोड़ों का विवाह करवाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।



शेख हसीना और दो करीबियों पर पहली जुलाई को तय होंगे आरोप

ढाका, 24 जून (एजेंसियां)।

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके दो शीर्ष सहयोगियों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-1 (आईसीटी-1) में आरोप नहीं तय हो सके। आईसीटी-1 ने कहा कि अब आरोप एक जुलाई को तय किए जाएंगे। शेख हसीना के अलावा पूर्व गृहमंत्री असदुज्जामा खान और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे। खबर के अनुसार आईसीटी-1 के जस्टिस मोहम्मद गोলাম मुर्तुजा मोजुमदार की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय

न्यायाधिकरण पीठ ने आदेश पारित किया कि भगोड़े आरोपितों असदुज्जामा और हसीना के लिए भी बचाव पक्ष के वकील नियुक्त किए जाएंगे। अभियोजन पक्ष ने पहली जून को तीनों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, यातना और घातक हथियारों के इस्तेमाल के अलावा अन्य आरोप लगाते हुए औपचारिक आरोप लगाए थे। न्यायाधिकरण ने पहली जून को ही आरोपों पर संज्ञान लेते हुए की तारीख मुर्करर की थी। अभियोजन पक्ष ने पहली जून को पीठ को बताया था कि शेख हसीना पांच अगस्त से भारत में हैं। असादुज्जामा भी वहीं छुपा हुआ है। पूर्व पुलिस प्रमुख मामून हिरासत में हैं।

अभियोजन पक्ष ने उन्हें पीठ के समक्ष पेश किया। तीनों पर मानवता के विरुद्ध अपराध के पांच आरोप लगाए गए हैं।

पहला आरोप: निहत्थे छात्र प्रदर्शनकारियों पर कानून प्रवर्तन और अवामी लोग के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा रोकने में विफल रहना। हिंसा करने वालों की सहायता करना। हत्या के लिए उकसाना। प्रदर्शनकारियों को यातना देना।

दूसरा आरोप: प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को दबाने के लिए घातक हथियारों (हेलीकॉप्टर और ड्रोन सहित) का उपयोग करने का आदेश देना।

तीसरा आरोप: अबू सईद की 16 जुलाई को

साजिशन हत्या करवाना।

चौथा आरोप: पांच अगस्त को ढाका के चंखरपुल में छह निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या करवाना।

पांचवां आरोप: पांच प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या करवाना। इसके बाद पांचों के शव को जलाने और एक अन्य प्रदर्शनकारी को जंदा जलाने की कोशिश करना।

इसके अलावा आईसीटी-1 ने हसीना और 10 अन्य के खिलाफ कुछ लोगों को जबरन गायब किए जाने के मामले में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी।

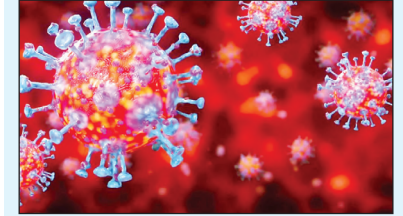
न्यूज़ ब्रीफ

कतर जाने वाली उड़ानों के रद्द होने से यात्रियों को काठमांडू एयरपोर्ट पर गुजारनी पड़ी रात



काठमांडू। कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान के हमले के बाद कतर द्वारा अपना एयरस्पेस बंद किए जाने के कारण बीती रात को काठमांडू से दोहा जाने वाली सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया। इसके कारण कतर जाने वाले यात्रियों को पूरी रात एयरपोर्ट पर ही गुजारनी पड़ी। काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल से दोहा की तरफ उड़ान भरने को तैयार कतर एयर, जजीरा एयर, नेपाल एयरलाइंस सहित कुछ अन्य विमानों की उड़ान नहीं हो पाने के कारण इन विमानों से यात्रा करने वाले लोगों को रात भर एयरपोर्ट पर ही गुजारनी पड़ी। एयरपोर्ट के प्रवक्ता तेज बहादुर पौडेल ने बताया कि रात 9 बजे नेपाल एयरलाइंस विमान से दोहा जाने वाले यात्रियों को बिठा दिया गया था लेकिन एयरस्पेस बंद होने की जानकारी मिलने के बाद सभी यात्रियों को नीचे उतार दिया गया। पौडेल ने बताया कि नेपाल से दोहा के लिए उड़ान भर चुके एक विमान को ओमान की राजधानी मस्कट की तरफ डायवर्ट किया गया था। यात्रियों ने डिपार्चर लाउज में गुजारी रात दोहा जाने वाली सभी विमानों की उड़ान रद्द होने के कारण यात्रियों को पूरी रात विमानस्थल पर ही गुजारनी पड़ी। रातभर एयरपोर्ट के डिपार्चर लाउज के बाहर सोने को मजबूर इन यात्रियों की शिकायत रही कि उनके बारे में न तो एयरलाइंस कंपनी के तरफ से और ना ही एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से उनके रुकने की कोई व्यवस्था की गई। यात्रियों का आरोप है कि फ्लाइट के पूरी तरह से कैसिल होने की जानकारी भी कई घंटे बाद दी गई।

नेपाल में पांच व्यक्तियों में कोविड-19 ओमिक्रोन के नए वेरिएंट की पुष्टि



काठमांडू। नेपाल के पांच लोगों में कोविड 19 के ओमिक्रोन के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। यह लोग पिछले दिनों भारत से लौटे हैं। नेपाल के स्वास्थ्य विभाग के महामारी विज्ञान और रोग नियंत्रण प्रभाग (ईडीसीडी) के अनुसार, भारत भेजे गए सैंपल में से पांच व्यक्तियों में कोविड-19 के ओमिक्रोन स्ट्रेन के एक नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। ईडीसीडी के प्रमुख डॉ. चंद्रबल झा ने बताया कि नए वेरिएंट की पहचान भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशाला में किए गए जीन अनुक्रमण परीक्षणों के माध्यम से की गई। उन्होंने बताया कि 5 जून से 12 जून के बीच कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए 14 व्यक्तियों से एकत्र किए गए नमूनों पर परीक्षण के लिए भेजा गया था। नए वेरिएंट को अत्यधिक संक्रामक माना जाता है। ईडीसीडी के आंकड़ों के अनुसार, मई 2025 के मध्य से अब तक नेपाल में कोविड-19 के कुल 167 मामलों की पुष्टि हुई है।

मध्य पूर्व में हवाई क्षेत्र बंद, दुबई और दोहा जा रही कम से कम 26 वाणिज्यिक उड़ानें डायवर्ट



दोहा/दुबई। मध्य पूर्व में सुरक्षा कारणों से हवाई क्षेत्र बंद होने के चलते सोमवार को दुबई (युएई) और दोहा (कतर) की ओर जा रही कम से कम 26 वाणिज्यिक उड़ानों का मार्ग बदलना पड़ा। विमानन विशेषण कंपनी सिरियम के अनुसार, डायवर्ट की गई उड़ानों में से 22 उड़ानें दोहा जा रही थीं, जबकि शेष चार दुबई की ओर थीं। इनमें से कुछ विमानों ने वैकल्पिक हवाई अड्डों पर लैंड किया, जबकि अन्य को अपने प्रस्थान स्थल पर लौटना पड़ा। सिरियम ने यह भी जानकारी दी कि दोहा की ओर डायवर्ट की गई उड़ानों में से 12 उड़ानों का संचालन कतर एयरवेज द्वारा किया जा रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उत्तरी अमेरिका से 39 उड़ानें और यूरोप से 210 उड़ानें सोमवार को मध्य पूर्व के लिए रवाना होने वाली थीं। हालांकि, यदि हवाई क्षेत्र शीघ्र नहीं खोला गया, तो इन उड़ानों के रद्द होने का खतरा बना हुआ है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य तनाव के चलते क्षेत्रीय सुरक्षा हालात बिगड़ गए हैं। कतर स्थित अल-उदीद अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान द्वारा मिसाइल हमले के बाद कई देशों ने एहतिyत के तौर पर अपने हवाई मार्ग बंद या सीमित कर दिए हैं।

ईरान और इजरायल के बीच हुआ युद्ध विराम डोनाल्ड ट्रंप बोले-उल्लंघन मत करना

तेहरान-तेल अवीव, 24 जून। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। इसकी जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। ट्रंप ने ट्विटर पर दोनों देशों के युद्ध विराम की घोषणा कर लिखा, युद्ध विराम अब प्रभावी है। कृपया इसका उल्लंघन न करें। वहीं, ईरान ने युद्ध विराम लागू होने से ठीक पहले इजरायल पर एक के बाद एक 15 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। ट्रंप ने जैसे ही युद्ध विराम की बात कही, ईरान ने इजरायल पर 6 बार हमले किए।

ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, तेहरान-इजरायल के बीच संघर्ष विराम सुबह 7:30 बजे लागू हुआ, उससे कुछ मिनट पहले ईरान ने इजरायल के भीतर मिसाइल हमलों का अंतिम दौर शुरू किया। इजरायल द्वारा ईरान की 6 मिसाइलों की पुष्टि करने बाद तेहरान ने कहा कि अब युद्ध विराम का समय शुरू हो गया है।

इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची ने इजराइल को अंतिम क्षण तक दंडित करने के लिए अपने सशस्त्र बलों को धन्यवाद दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार सुबह ईरान की ओर से 6 बार में 10 से 15 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है, जिसमें से अधिकांश को रोक दिया गया। एक मिसाइल बीशेबा शहर में एक अपार्टमेंट पर गिरी, जिससे अपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हो गया और हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। मलबे से बाद में एक महिला का शव निकाला गया है। हमले में 6 लोग घायल हुए हैं। इजरायल ने सभी शहरों में सायरन बजा दिए हैं।

एक तरफ युद्ध विराम से पहले ईरान इजरायल पर लगातार मिसाइल हमले कर रहा था, वहीं दूसरी ओर ट्रंप युद्ध रोकने का श्रेय ले रहे थे। उन्होंने हमलों के दौरान ट्विटर पर लिखा, हम अपने महान बी-2 पायलटों और उस ऑपरेशन से जुड़े



ईरान के हमले पर सऊदी अरब का कड़ा विरोध, कतर के समर्थन में उतरा

रियाद/दोहा। सऊदी अरब ने कतर में स्थित अल-उदीद सैन्य अड्डे पर ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। सऊदी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह हमला अंतरराष्ट्रीय कानून और सद्भावपूर्ण पड़ोसी संबंधों के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। बयान में कहा गया, राज्य ईरान के इस प्रतिशोधात्मक हमले की कड़ी निंदा करता है और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन मानता है। यह हमला क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। सऊदी अरब ने यह भी स्पष्ट किया कि वह कतर के साथ पूर्ण एकजुटता के साथ खड़ा है और भाईचारे की भावना के तहत कतर द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम में उसका पूर्ण समर्थन करेगा। सऊदी अरब का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान ने अमेरिकी परमाणु टिकानों पर हमले के जवाब में कतर स्थित अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागीं थीं, जिन्हें कतर की वायु रक्षा प्रणाली ने रोक लिया था। हालांकि हमले में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इससे खाड़ी क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया है।



सभी लोगों की प्रतिभा और साहस के बिना आज का सौदा नहीं कर पाते। निश्चित और बहुत विडंबनापूर्ण तरीके से, देर शाम को उस बेहतरीन हमले ने सभी को एक साथ ला दिया, और सौदा

हो गया!!! युद्ध विराम लागू होने के अंतिम समय में ईरान के घातक मिसाइल हमलों के बाद इजरायल का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, इससे जवाबी हमले की आशंका है।

जेफ बेजोस और लॉरेन सांचेज की प्री-वेडिंग में पाजामा पार्टी, शादी 27 जून को



अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस इस हफ्ते पत्रकार लॉरेन सांचेज से शादी करने जा रहे हैं। शादी से पहले होने वाली प्री-वेडिंग पार्टियों की तैयारी चल रही है। इनमें तीन अलग-अलग थीम वाली पार्टियां शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार जेफ बेजोस और लॉरेन सांचेज की शादी का जश्न कई दिनों तक चलेगा। पाजामा पार्टी से लेकर फोम पार्टी तक। सब कुछ शादी अंदाज में होगा। जेफ और लॉरेन की शादी 27 जून को होने वाली है। यह शादी इटली के खुबसूरत शहर वेनिस में होगी। इससे पहले एक पजामा पार्टी होगी। एक जानकारी ने बताया, मेहमानों को कई तरह के कापड़े और सामान लाना होगा, क्योंकि अलग-अलग थीम के कार्यक्रम होंगे। हाल ही में लॉरेन के बेटे इवान के 19वें जन्मदिन पर बेजोस ने अपने सुपरयॉट पर एक फोम पार्टी करवाई। तस्वीरों में दोनों यूरोप के तट के पास झगम में नाचते हुए दिखे। शादी में ओप्रा विंफ्रे, बारबरा स्ट्राइसैंड, इवांका ट्रम्प, औरलैंडो ब्लूम जैसे बड़े सितारे शामिल होंगे। इनके लिए कॉकटेल पार्टी, रिवर्सल डिनर और रिसेप्शन जैसे कार्यक्रम होंगे।

रूसी हमले में यूक्रेन में 13 नागरिकों की मौत जेलेन्स्की ने पश्चिमी देशों से मदद मांगी

कीव, 24 जून (एजेंसियां)।

यूक्रेन में रूस के ड्रोन, मिसाइल और तोपखाने से हुए हमलों में कम से कम 13 नागरिकों की मौत हो गई और लगभग 100 लोग घायल हुए हैं। यह जानकारी यूक्रेनी अधिकारियों ने मंगलवार को दी। इन हमलों के बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की ने पश्चिमी देशों से और सैन्य मदद की मांग की है। वह मंगलवार को नीदरलैंड्स के हेग शहर में नाटो शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे नेताओं से मिलेंगे। उनका मकसद यूक्रेन की सुरक्षा के लिए भविष्य की सहायता सुनिश्चित करना है। मंगलवार दोपहर रूस ने यूक्रेन के झिप्रो शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। जिसमें सात नागरिकों की मौत हुई और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं पास के समर शहर में भी हमला हुआ, जिसमें दो लोगों की मौत हुई और नौ लोग घायल हुए।



झिप्रो के मेयर बोसिस फिलाटोव ने बताया कि इस हमले में 19 स्कूल, 10 किंडरगार्टन, एक संगीत विद्यालय, एक सामाजिक सेवा कार्यालय और आठ मेडिकल सेंटर क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं दक्षिणी खेरसॉन इलाके में चार नागरिक मारे गए और 11 घायल हुए। जबकि उत्तर-पूर्वी सूमी क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक बच्चे समेत तीन नागरिक मारे गए। जबकि घायलों में दो 17 साल

की लड़कियां और एक 12 साल का लड़का भी शामिल हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने रातभर में 20 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, जिनमें से 14 ड्रोन कुरस्क इलाके में और दो ड्रोन मॉस्को क्षेत्र में थे। एक ड्रोन मॉस्को के एक टावर ब्लॉक से टकराया, जिससे 17वीं मंजिल पर आग लग गई। इस दौरान एक 34 वर्षीय व्यक्ति को हाथ और पैर में छर्रे लगे। दो अन्य ड्रोन मॉस्को पहुंचने से पहले ही गिरा दिए गए। इन खतरों के चलते मॉस्को के दो बड़े एयरपोर्ट- वनूकोवो और शेरेमेतेवो- पर हवाई यातायात को कुछ समय के लिए रोका गया। राष्ट्रपति जेलेन्स्की की चिंता इस बात को लेकर भी है कि बाइडन प्रशासन की तरफ से भी कई सैन्य सहायता जल्द ही खत्म हो सकती है, और यह स्पष्ट नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका मदद देगा या नहीं।

ईरान के परमाणु हथियार नष्ट करने का संकल्प ले चुके इजराइल के पास हैं 200 बम

वाशिंगटन, 23 जून (एजेंसियां)।

किसी से छिपी नहीं है कि दशकों से इजरायल को पश्चिम एशिया का एकमात्र ऐसा देश माना जाता रहन है, जिसके पास परमाणु हथियार हैं, भले ही उसके नेताओं ने इन हथियारों की मौजूदगी की पुष्टि या खंडन करने से इनकार कर दिया है। इसी इजरायल का कहना है कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के प्रति दृढ़ है, क्योंकि गुप्त रूप से परमाणु हथियार तैयार करने में जुटा उसका कट्टर दुश्मन उसके अस्तित्व के लिए खतरा है।

इजरायल उन पांच देशों में से एक है, जो वैश्विक परमाणु अप्रसार संधि का हिस्सा नहीं हैं।



इससे उसे निरस्त्रीकरण करने या यहां तक कि निरीक्षणों को उसके देश में मौजूद परमाणु केंद्रों की जांच करने की अनुमति देने से जुड़े अंतरराष्ट्रीय दबाव से राहत मिलती है।

वर्ष 1986 में इजरायल की अस्पष्टता की नीति को बड़ा झटका लगा, जब परमाणु केंद्र पर मौजूद एक पूर्व तकनीशियन मोर्दके वानुनू ने डिमोना की गतिविधियों को उजागर किया। तस्वीरें और

विवरण उपलब्ध कराए। वानुनू को देशद्रोह के आरोप में 18 साल जेल में रखा गया और उसे विदेशियों से मिलने या देश छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इजरायल के पास 80 से 200 परमाणु हथियार हैं। ईरान और अन्य जगहों पर आलोचकों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त नजर रखने के लिए पश्चिमी देशों पर पाखंड का आरोप लगाया है, जबकि इजरायल के सख्त शस्त्रागार को खुली छूट दी जा रही है। इजरायल ने 1958 में देश के पहले नेता प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के नेतृत्व में सुदूर रीमस्तानी शहर डिमोना में अपना नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र खोला। उनका मानना था कि पड़ोस में शत्रु देशों से घिरे छोटे से नवोदित देश को सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय के रूप में परमाणु निरोध की आवश्यकता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इनका इस्तेमाल केवल आपातकालीन स्थिति में, अंतिम उपाय के रूप में किया जाना था।

विशेषज्ञों का कहना है कि इजरायल की अस्पष्टता ने उसे ईरान और अन्य दुश्मनों के खिलाफ अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में सक्षम बनाया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, इजरायल ने यह क्षमता क्षेत्रीय स्तर पर परमाणु हथियारों की दौड़ को बढ़ावा दिए बिना या एहतिyयता हमलों (संभावित हमले से बचने के लिए किये गए हमले) को आमंत्रित किए बिना हासिल की है। एक लेख के अनुसार, इस परमाणु केंद्र के खुलने के बाद इजरायल ने डिमोना में काम को एक दशक तक छिपाए रखा और अमेरिका के अधिकारियों से कहा कि यह एक कपड़ा काखाना है। 'फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स' के परमाणु सूचना परियोजना के निदेशक हैंस एम। क्रिस्टेंसन और इसी संगठन के शोधकर्ता मैट कोर्डा द्वारा सह-लिखित इस लेख के अनुसार, डिमोना में उत्पादित प्लूटोनियम पर निर्भर रहते हुए इजराइल के पास 1970 के दशक के प्रारंभ से ही परमाणु हथियार दागने की क्षमता है।



अमेरिका और ईयू के साथ जल्द ही व्यापार समझौते संपन्न होने की उम्मीद : वित्त मंत्री

नई दिल्ली, 24 जून (एजेंसियां)।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है, जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

वित्त मंत्री ने राजधानी नई दिल्ली में एक्जिम बैंक ट्रेड कॉन्क्लेव 2025 के दौरान विकसित भारत के लिए निर्यातों-मुख विकास विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने पहले ही संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और चार देशों के यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) ब्लॉक के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर कर लिए हैं, जबकि ब्रिटेन के साथ बातचीत पूरी हो चुकी है।

इंडिया एक्जिम बैंक के व्यापार सम्मेलन को

संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब अधिक मुक्त व्यापार समझौते करने पर जोर दिया जा रहा है। सीतारमण ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ बातचीत वास्तव में बेहद तेजी से जारी है और जल्द ही निष्कर्ष पर पहुंच जाएगी। वर्ष 2030 तक 2,000 अरब अमेरिकी डॉलर के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए निर्यात को बढ़ावा देने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

वित्त मंत्री ने देश के निर्यात का उल्लेख करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में वस्तुओं

एवं सेवाओं का कुल निर्यात 825 अरब अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में छह फीसदी की वृद्धि है। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2013-14 के 466 अरब अमेरिकी डॉलर से एक महत्वपूर्ण छलांग है। जहां वैश्विक निर्यात में केवल चार फीसदी की वृद्धि हुई है। वहीं, भारत के निर्यातक व्यापार मोर्चे पर वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद तेजी से आगे बढ़ने और 6.3 फीसदी की वृद्धि को पार करने में सफल रहे हैं।

न्यूज़ ब्रीफ

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों को देना होगा 1,225 रुपए तक यूडीएफ



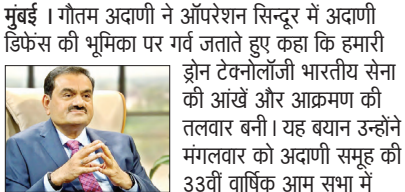
मुंबई। भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ईआरए) ने निर्माणाधीन नवी मुंबई हवाई अड्डे पर 1,225 रुपये तक का उपयोगकर्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) लगाने की अनुमति दे दी है। इस हवाई अड्डे का विकास नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (एनएमआईएल) द्वारा किया जा रहा है। इस वर्ष के अंत में चालू होने वाले इस हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाले यात्रियों को घरेलू उड़ानों के लिए 620 रुपये और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 1,225 रुपये उपयोगकर्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) के रूप में देने होंगे। ईआरए के 42 पृष्ठ के आदेश के अनुसार, हवाई अड्डे पर उतरने वाले यात्रियों के लिए घरेलू और विदेशी उड़ानों के लिए यूडीएफ क्रमशः 270 रुपये और 525 रुपये होगा। यूडीएफ शुल्क को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तदर्थ आधार पर अनुमोदित किया गया है। ईआरए ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक या नियमित शुल्क के अंतिम निर्धारण तक अंतरिम उपाय के रूप में तदर्थ यूडीएफ लगाने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

एकमे सोलर की राजस्थान में 300 मेगावाट की सीकर परियोजना चालू



नई दिल्ली। एकमे सोलर होल्डिंग्स ने राजस्थान में सीकर सौर परियोजना में 60 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़ते हुए अपनी 300 मेगावाट की इस परियोजना शुरू कर दी है। कंपनी ने मंगलवार को घोषणा की कि इस तिमाही के शुरू में कंपनी ने परियोजना की कुल 300 मेगावाट क्षमता में से 240 मेगावाट को आंशिक रूप से चालू कर दिया। इस उपलब्धि के साथ एकमे सोलर की कुल परिचालन क्षमता बढ़कर 2,890 मेगावाट हो गई है। बयान के अनुसार एकमे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड ने अतिरिक्त 60 मेगावाट क्षमता चालू करने के बाद राजस्थान में एकमे सीकर सौर परियोजना में अपनी 300 मेगावाट की पूरी अक्षय ऊर्जा क्षमता चालू कर दी है। भारत के सबसे अधिक सौर विकिरण क्षेत्रों में से एक राजस्थान के बीकानेर में 1300 एकड़ में फैली यह परियोजना 220 कवी पर बीकानेर-2 सबस्टेशन से जुड़ी है। इससे प्रतिवर्ष करीब 78 करोड़ युनिट (एमयू) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है।

आदानी डिफेंस बनी सेना की आंख और ढाल



मुंबई। गौतम अदाणी ने ऑपरेशन सिन्दूर में अदाणी डिफेंस की भूमिका पर गर्व जताते हुए कहा कि हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी भारतीय सेना की आंखें और आक्रमण की तलवार बनी। यह बयान उन्होंने मंगलवार को अदाणी समूह की 33वीं वार्षिक आम सभा में दिया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिन्दूर ने हमें याद दिलाया कि शांति मुफ्त नहीं मिलती है, हम वही खड़े होते हैं। हमारी एटी-ड्रोन प्रणाली ने सैनिकों और नागरिकों दोनों की रक्षा की। गौरतलब है कि यह सैन्य अभियान 7 मई को कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया था। मुंबई एयरपोर्ट ने जुटाए 750 मिलियन डॉलर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएल), जो अदाणी समूह के अधीन है, ने न्यूयॉर्क स्थित एपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के नेतृत्व में निवेशकों के एक समूह से 750 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। इस राशि का उपयोग घरेलू कर्ज चुकाने और एयरपोर्ट के विस्तार कार्यों के लिए किया जाएगा। अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के सीईओ अरुण बंसल ने कहा, इस फंडिंग से हमें ऑपरेशनल लचीलापन मिलेगा और हम यात्रियों की और बेहतर अनुभव देने की दिशा में तेजी से काम कर सकेंगे। मुंबई एयरपोर्ट अब अगले पांच वर्षों में करीब 10,000 करोड़ का निवेश करेगा, जिससे इसकी वार्षिक क्षमता 54.8 मिलियन से बढ़कर 229 मिलियन यात्रियों तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा, अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने इसी महीने बार्कलेज, फर्स्ट अबू धाबी बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे अंतरराष्ट्रीय बैंकों से भी 750 मिलियन डॉलर जुटाए थे, जिसमें से 400 मिलियन कर्ज चुकाने और बाकी देशभर के छह एयरपोर्ट्स के विकास में उपयोग किया जाएगा।

एसएंडपी ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर किया 6.5 फीसदी

नई दिल्ली, 24 जून (एजेंसियां)।

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.5 फीसदी कर दिया है।

रेटिंग्स एजेंसी ने मंगलवार को जारी एशिया प्रशांत आर्थिक परिदृश्य में सामान्य मानसून, कच्चे तेल की कम कीमतों और मौद्रिक नरमी को ध्यान में रखते हुए विकास दर के अनुमान में ये इजाफा किया है। हालांकि, एसएंडपी ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरों की भी आशंका जताई है। एसएंडपी ने पिछले महीने वैश्विक अनिश्चितताओं और अमेरिकी टैरिफ झटकों का हवाला देते हुए चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 20 आधार अंकों (0.20 फीसदी) घटाकर 6.3 फीसदी कर दिया था।

एजेंसी ने जारी अपने ताजा अनुमान में कहा कि अगर पश्चिम एशिया में संघर्ष लंबा खिंचा तो इससे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं जिसका एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र के आर्थिक विकास पर असर होगा। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए 90 फीसदी आयात पर निर्भर है और अपनी प्राकृतिक गैस का लगभग आधा हिस्सा विदेशों से खरीदता है। एसएंडपी ने कहा कि घरेलू मांग में लचीलापन, भारत जैसी वस्तुओं के निर्यात से कम जुड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक मंदी को सीमित करने में विशेष रूप से प्रसंगिक है।

एसएंडपी ने कहा कि हमें लगता है कि 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5 फीसदी रहेगी। इस पूर्वानुमान में सामान्य मानसून, कच्चे तेल की कम कीमतें, आयकर में छूट और मौद्रिक सहजता को शामिल किया गया है। भारत के लिए एसएंडपी का विकास दर का ताजा अनुमान रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा इस महीने की शुरुआत में जताए गए 6.5 फीसदी के अनुमान के अनुरूप है।



यूपीआई से फेल ट्रांजेक्शन पर मिलेगा तुरंत रिफंड, 15 जुलाई से लागू होगा नया नियम

मुंबई। यूपीआई 15 जुलाई से नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) नया चार्जबैक नियम लागू करने जा रहा है, जिसके तहत अगर किसी लेनदेन में पैसा खाते से कट गया लेकिन भुगतान नहीं हुआ, तो ग्राहक को तुरंत रिफंड मिल जाएगा। अब इसके लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर यूपीआई ट्रांजेक्शन फेल होता है लेकिन खाते से पैसा कट जाता है, तो यूजर को तुरंत पैसा वापस मिल जाएगा। वहीं यूजर बैंक से पैसा वापस मांग सकेगा, जिससे गलत ट्रांसफर के मामलों में तेजी से समाधान मिलेगा। अब बैंक एनपीसीआई की पूर्व अनुमति के बिना भी कुछ अस्वीकृत चार्जबैक को फिर से उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे। एनपीसीआई की नई व्यवस्था के तहत पुराने मामलों की भी दोबारा जांच की जा सकेगी। जिन ग्राहकों के चार्जबैक दावे पहले खारिज हो चुके हैं, उन्हें भी समाधान की उम्मीद मिलेगी।



अगले साल फरवरी से शुरू होगा घरेलू आय सर्वेक्षण



सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अगले साल फरवरी से घरेलू आय सर्वेक्षण (एचआईएस) शुरू करने की योजना बना रहा है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजित सिंह ने कहा कि ग्रामीण और शहरी परिवारों की औसत आय का अनुमान लगाने के उद्देश्य से मंत्रालय ने फरवरी 2026 से घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने की योजना बनाई है। ग्रामीण-शहरी परिवारों की औसत आय का होगा आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) का यह सर्वेक्षण भारतीय परिवारों की आय संबंधी आंकड़े जुटाने के नए प्रयासों को दर्शाता है। यह अभी इस्तेमाल हो रहे घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के मुकाबले देश में जीवन स्तर, गरीबी, आय एवं धन संबंधी असमानताओं और उपभोक्ता व्यवहार की बेहतर तस्वीर प्रदान करेगा। एक अधिकारी ने नाम नहीं छपाने की शर्त पर कहा कि प्रस्तावित सर्वेक्षण उपभोग व्यय सर्वेक्षण की जगह नहीं लेगा। आय सर्वेक्षण मुश्किल है, लेकिन समिति कुछ अन्य देशों द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली पर काम कर रही है और सीख रही है। परिवारों से जानकारी हासिल करना एक चुनौती होगी मगर समिति सभी पहलुओं पर गौर कर रही है।

नई दिल्ली, 24 जून (एजेंसियां)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर होने का एलान करने के कारण ग्लोबल मार्केट से मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान मजबूती के साथ बंद होने में सफल रहे। डाउ जॉन्स स्पूचर्स भी बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के एलान के पहले बंद होने की वजह से यूरोपीय बाजारों में पिछले सत्र के दौरान बिकवाली का दबाव बना रहा। वहीं एशियाई बाजारों में चोतरफा तेजी नजर आ रही है।

ईरान और इजराइल के बीच पिछले 12 दिन से जारी संघर्ष के थमने का एलान करके डोनाल्ड ट्रंप ने निवेशकों के बीच उत्साह का माहौल बना दिया, जिसके कारण वॉल स्ट्रीट के सूचकांक पिछले सत्र के दौरान मजबूती के साथ बंद होने में सफल रहे। एस एंड पी 500 इंडेक्स 0.96 प्रतिशत की मजबूती के साथ 6,025.17 अंक के स्तर पर बंद हुआ।



ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत, एशिया में भी तेजी का रुख

इसी तरह नैस्डेक ने 183.56 अंक यानी 0.94 प्रतिशत की तेजी के साथ 19,630.97 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। डाउ जॉन्स स्पूचर्स फिलहाल 223.26 अंक यानी 0.52 प्रतिशत उछल कर 42,805.04 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान लगातार दबाव बना रहा। एफटीएसई इंडेक्स 0.19 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 8,758.04 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसई इंडेक्स ने 0.69 प्रतिशत की गिरावट के साथ 7,537.57 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएएक्स इंडेक्स 0.35 प्रतिशत टूट कर 23,269.01 अंक के स्तर पर बंद हुआ। एशियाई बाजार में चोतरफा खरीदारी होती नजर आ रही है। एशिया के सभी 9 बाजारों के सूचकांक मजबूती के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। निफ्ट 256.50 अंक यानी 1.02 प्रतिशत उछल कर 25,234.50 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा

है। इसी तरह निक्केई इंडेक्स 404.06 अंक यानी 1.04 प्रतिशत की तेजी के साथ 38,758.15 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। कोस्पी इंडेक्स ने बड़ी छलांग लगाई है। फिलहाल यह सूचकांक 2.78 प्रतिशत की बढ़त के साथ 3,100.61 अंक के स्तर पर कारोबार करता रहा है। इसी तरह हैंग सेंग इंडेक्स 483.34 अंक यानी 2 प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,172.47 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा सेट कंपोजिट इंडेक्स 1.96 प्रतिशत उछल कर 1,083.99 अंक के स्तर पर, जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स 115.38 अंक यानी 1.67 प्रतिशत की तेजी के साथ 6,902.52 अंक के स्तर पर, ताइवान टैटेड इंडेक्स 361.98 अंक यानी 1.64 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22,094 अंक के स्तर पर, शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.98 प्रतिशत की छलांग लगा कर 3,415.05 अंक के स्तर पर और स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.43 प्रतिशत की मजबूती के साथ 3,896.06 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

भारत से 10 अरब डॉलर के उत्पाद मंगाने आपूर्तिकर्ताओं के साथ काम जारी: वॉलमार्ट सीईओ



नई दिल्ली, 24 जून (एजेंसियां)।

वॉलमार्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (वैश्विक) डग मैकमिलन ने मंगलवार को कहा कि उनकी कंपनी अपने वैश्विक परिचालन के लिए भारत से 10 अरब डॉलर का सामान मंगाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत में आपूर्तिकर्ताओं के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वॉलमार्ट ने पिछले कुछ वर्षों में भारत से अपनी खरीद बढ़ा दी है और वह इस प्रगति से उत्साहित है।

पिछले कुछ वर्षों में आप देख सकते हैं कि स्थिति कैसे बदल रही है और यह वास्तव में व्यापक और अधिक दिलचस्प होती जा रही है। बेंगलुरु के मुख्यालय वाली खुदरा दिग्गज कंपनी ने 2027 तक भारत से 10 अरब डॉलर डॉलर के उत्पाद मंगाने का लक्ष्य रखा है जिसका उद्देश्य परिधान, खाद्य, खिलौने और अन्य श्रेणियों में निर्यात को बढ़ावा

देना है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में हम यहां से सीमित श्रेणियों के उत्पाद ले रहे थे, लेकिन अब हम इसका विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं। सीईओ ने कहा कि इसमें काफी वृद्धि हुई है और अब हमारा लक्ष्य इसे प्रति वर्ष 10 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है, जो वास्तव में एक बड़ा आंकड़ा है और आपूर्तिकर्ता समुदाय के साथ मिलकर हम इसे प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। डग मैकमिलन दो दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। यहां उन्होंने वॉलमार्ट की भारत में विकास गाथा का उल्लेख किया जिसमें निर्यात, डिजिटल नवाचार, समावेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण व समुदायों को सशक्त बनाना शामिल है। इसके अलावा, उन्होंने कुछ विक्रेताओं से भी बातचीत की जिन्हें आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम वॉलमार्ट वुडि के तहत प्रशिक्षित किया गया है।



इस योजना को 15 मार्च, 2024 की अधिसूचना से अधिसूचित किया गया था, जो विस्तृत योजना दिशा-निर्देश बाद में अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2450 (ई) दिनांक 02.06.2025 को जारी किए गए थे। अधिसूचना और दिशा-निर्देश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। मंत्रालय के मुताबिक इस संदर्भ में योजना के तहत पात्र आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और आवेदक पर आवेदन मांड्यूल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन पोर्टल 24 जून को सुबह 10.30

बजे से आवेदनों के लिए खुलेगा और 21 अक्टूबर, 2025 को शाम 06 बजे तक खुला रहेगा। उल्लेखनीय है कि यह योजना भारत को इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार की गई है। घरेलू मूल्य संवर्धन लक्ष्यों को अनिवार्य करके, यह योजना 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहलों को और बढ़ावा देगी, साथ ही वैश्विक और घरेलू दोनों कंपनियों को भारत की हरित गतिशीलता क्रांति में सक्रिय भागीदार बनने के लिए सशक्त बनाएगी।

835 रन बनाकर भी टीम इंडिया ने घुटने टेके, इंग्लैंड ने हार के लिए किया मजबूर, याद आए 'कप्तान' रोहित

लार्ड्स, 24 जून (एनएसआर)। इंग्लैंड ने टेस्ट इतिहास का 10वां सबसे बड़ा रन चेज कर लिया है। हेडलैंड के मैदान पर भारत ने 371-खिरी पारी में इंग्लैंड को जीत के लिए 371-रनों का लक्ष्य दिया था। बेन स्टोक्स की टीम ने 5 विकेट खोकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। यह भारत के खिलाफ टेस्ट इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा रन चेज है। सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड भी इंग्लैंड के नाम है। 2022 में बर्मिंघम में इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ चौथी पारी में 378 रनों का टारगेट हासिल कर लिया था। ये दोनों टेस्ट में इंग्लैंड के दो सबसे बड़े रन चेज हैं। मैच की पहली



पारी में भारत ने 471 रन बनाया था। इसके बाद इंग्लैंड ने 465 रन ठोके। भारतीय टीम की दूसरी पारी 364 रनों पर समिट गई थी। इससे तरह इंग्लैंड को जीत के लिए 371 रनों का लक्ष्य मिला। इस जीत से इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज-नैटदुलकर ट्रॉफी में 1-0 की बढ़त बना ली है। यह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में भारत का पहला मैच था। शुभमन गिल की कप्तानी में यह भारत का पहला ही टेस्ट था। इस मैच के साथ गिल-शंभरी युग की शुरुआत हुई है लेकिन टीम को भारतीय हवा गिरा। भारत ने मैच में 835 रन बनाए। टीम की तरफ से बल्लेबाजों ने 5 शतक

लागा। आज तक किसी भी टेस्ट में भारत की तरफ से 5 शतक नहीं लगे थे। इसके बाद भी टीम इंडिया का मुक़ाबला हारना काफी शर्मनाक है। भारत को इससे पहले सिर्फ एक बार ही अपनी पहली पारी में इससे बड़ा स्कोर बनाने के बाद हार मिली थी। 2008 के सिडनी टेस्ट में 532 रन बनाकर के बाद भी ऑस्ट्रेलिया से भारत हार गया था। अब तक टेस्ट इतिहास में सिर्फ चार ही बार कोई टीम 835 रन से ज्यादा बनाने के बाद भी मैच हारी। इंग्लैंड 1948 में इसी मैदान पर 861 रन बनाने के बाद हारी थी 2022 में पाकिस्तान 847 और न्यूजीलैंड 837 रन

बनाने के बाद इंग्लैंड से हारी थी।
इंग्लैंड की तरफ से चौथी पारी में बेन डकेट ने तूफानी शतक ठोका। सलामी बल्लेबाजी करने उतरे डकेट ने 149 रनों की पारी खेली। सिर्फ 170 गेंदों पर उन्होंने 21 चौके और एक छक्का लगाया। यह टेस्ट मैच की चौथी पारी में भारत के खिलाफ किसी भी बल्लेबाज का सबसे बड़ा स्कोर है। पहले विकेट के लिए डकेट ने जैक क्रॉउली के साथ 188 रनों की साझेदारी बनाई। यह टेस्ट इतिहास में इंग्लैंड के लिए चौथी पारी में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी रही। जो रूट 53 जबकि जेमी स्मिथ 44 रन बनाकर नाबाद रहे।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

किशनगंगा और...

नहर बनाने की योजना तैयार की है। इसने जम्मू-कश्मीर में चेनाब पर दो रन-ऑफ-द-रिवर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बगालिहार और असम के लाला में दो फ्लशिंग एक्ससराइड शी की है। सिंधु जल संधि को फलदात भारत बड़ी योजना पर काम करने जा रहा है। केंद्रीय उर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में ऐसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स शुरूआती चरण में हैं, उनमें ज्यादा पानी के स्टोरेज की योजना बनाई जाएगी लेकिन वे परियोजनाएं जो पहले से पावरप्लाइन में हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि उनकी तकनीकी जानकारीयें फाइनल की जा चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसी जाण परियोजनाएं जो अभी शुरूआती चरण में हैं, उनमें हम ज्यादा पानी स्टोर करने और बिजली उत्पादन की योजना बना सकते हैं। पहलगात आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला किया था। इस संधि के तहत हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में ज्यादा पानी स्टोर नहीं किया जा सकता लेकिन अब सरकार नई परियोजनाओं में स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने की तैयारी है। हैमोीजूदा वक्त में जम्मू-कश्मीर में चार हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (सीईए) से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इन पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। इनमें सिंधु नाला पर न्यू गांदरबार (१३ मेगावाट), चेनाब पर किशतई-२ (१३० मेगावाट) और सावलकोट (१,८५६ मेगावाट) तथा झेलम पर उरी-१ चरण-२ (२४० मेगावाट) शामिल हैं। केंद्र सरकार चेनाब पर चार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स- पाकल दुल (१,००० मेगावाट), रतले (८५० मेगावाट), किरू (६२४ मेगावाट) और क्कार (५४० मेगावाट) को तेजी से पूरा करना चाहती है। पाकल दुल जम्मू-कश्मीर में बनने वाला पहला स्टोरेज पर आधारित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इसके पूरा होने पर इसके पानी स्टोर करने की क्षमता लगभग १०९ मिलियन क्यूबिक मीटर होगी और इसे सितंबर २०२६ तक शुरू करने का लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी प्रोजेक्ट के लिए साइबर सिक्योरिटी को मजबूत किया जा रहा है, चाहे वह ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर पावर जेनरेशन हो।

सिंधु जल संधि तकरिबन 65 सालों से चली आ रही है। इसके तहत सिंधु नदी प्रणाली को साझा किया जाता है। भारत के लिए पश्चिमी नदियाँ सतलज, व्यास और रावी व पाकिस्तान के लिए पश्चिमी नदियाँ सिंधु, झेलम और चेनाब नदी हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के कुछ वर्षों ने दावा किया है कि यह संधि उनके देश के लिए सही नहीं है और दूसरे के लिए बहुत उदार है। जब इस पर साइन किए गए थे तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे पाकिस्तान के लिए शांति की कीमत बताया था। अब भारत इसे पूरी तरह से खत्म करने के बारे में विचार कर रहा है। सिंधु जल संधि पर दोनों देशों ने साइन किए थे। उस वक्त से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। अब अगर इस पर अगले बढ़ना है तो संधि पर न सिर्फ बातचीत करने की जरूरत है। पुरानी संधि के हिसाब से पाकिस्तान को ज्यादा पानी मिला। पश्चिमी नदियों में पानी का औसत वार्षिक प्रवाह पूर्वी नदियों से चार गुना ज्यादा है। लेकिन यहां पर दो बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। भारत को पूर्वी नदियों के पानी का खास इस्तेमाल चाहिए था। भारत ने तब से इन नदियों पर बांध और अन्य वाटर प्रोजेक्ट बनाए हैं। इनमें भाखड़ा नांगल बांध और राजस्थान नहर परियोजना शामिल है। इसको अब इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है। इस नहर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सिंचाई में मदद मिली है।

बल्लू में पाकिस्तान का तीन पश्चिमी नदियाँ स पानी के प्रवाह को एक बाढ़ हिस्सा मिला, लेकिन भारत को इन नदियों पर कुछ इस्तेमाल नहीं है। जैसे थेरेलू इस्तेमाल, खेती के इस्तेमाल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का अधिकार था। हमने इसका पूरा इस्तेमाल नहीं किया। साथ ही, भारत को पश्चिमी नदियों पर 3.6 मिलियन एकड़ फीट तक जल का अधिकार है। सलाल और बागलिहार बांधों पर केवल 7 मिलियन एकड़ फीट की कैपेसिटी हासिल की गई है। एकलदह बांध के पूरा होने के साथ स्टोरेज कैपेसिटी को .8 एकड़ फीट तक बढ़ाने की प्लानिंग है। यह भी बाद रखना चाहिए कि सिंधु पर सिविल इंजीनियरों ने बातचीत की थी, राजनेताओं और राजनयिकों ने नहीं। सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद भारत सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली परियोजनाओं में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अडंगा डालने की कोशिश शुरू कर दी है। उनका कहना है कि सिंधु का पानी किसी अन्य राज्य के साथ साझा नहीं किया जा जाएगा। उल्लेखनीय है कि भाखड़ा-नांगल प्रोजेक्ट के पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद अभी भी जारी है। वहीं पंजाब और उसके उत्तरी पड़ोसी राज्य जम्मू-कश्मीर के बीच जल बंटवारे को लेकर एक और विवाद पनप रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा यह घोषणा किए जाने के कुछ दिनों बाद कि सिंधु नदी का पानी तीन साल के भीतर नहरों के माध्यम से राजस्थान के श्रीगंगानगर तक ले जाया जाएगा। इसका जम्मू-कश्मीर के सीएम ने जमकर विरोध किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, अभी जम्मू में पानी की कमी है। जलनों में पानी नहीं है। मुझे पंजाब को पानी क्यों भेजना चाहिए? सिंधु जल संधि के अनुसार पंजाब में पहले से ही तीन नदियाँ हैं। क्या पंजाब ने हमें कोई पानी दिया है। जम्मू-कश्मीर सीएम का यह बयान उस प्रस्ताव के खिलाफ आया जिसमें सिंधु जल संधि की पश्चिमी नदियाँ सिंधु, झेलम और चेनाब का अतिरिक्त पानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक पहुंचाने के लिए 113 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं मंजूरी नहीं देने जा रहा हूँ। पहले हमें अपना पानी इस्तेमाल करने दिया जाना, फिर हम दूसरों के बारे में बात करेंगे। जल-बंटवारे की योजना में जिन तीन नदियों का उल्लेख किया गया है, उनमें पंजाब को शामिल किए जाने पर सीएम ने सवाल उठाया। उमर ने कहा, मुझे पंजाब को पानी क्यों भेजना चाहिए? सिंधु जल संधि के तहत पंजाब के पास पहले से ही पानी है। आया उन्होंने हमें तब पानी दिया जब हमें इसकी जरूरत थी। उन्होंने अपराध लगाया कि पंजाब ने जो प्रमुख परियोजनाओं, उमर शाहपुर कंडी पर जम्मू-कश्मीर को सालों तक ईंटागर कारवाया। उमर ने कहा, तीनों नदियों का पानी हमारे लिए है। हम इसका इस्तेमाल

अपने लिए करेंगे और फिर दूसरों के बारे में सोचेंगे।

इस पर पंजाब के राजनीतिक दलों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला एकतरफा फैसला नहीं ले सकते। राज्य में पार्टी के प्रवक्ता नली गर्ग ने कहा, 'जब भी युद्ध होता है, पंजाब युद्ध का मैदान बन जाता है और जब देश को खाद्यान्न की जरूरत होती है, तो यह देश का अन्न भंडार बन जाता है। अब जब पानी उपलब्ध है, तो पंजाब का इस पर वैध दावा है।' पंजाब कांग्रेस के चीफ अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने भी उमर के बयान पर आलोचना की। उन्होंने कहा, यह दुःख है कि जम्मू-कश्मीर के सीएम ने पाकिस्तान को पानी जाने से रोकने के लिए प्रस्तावित नहीं पर राजनीति करना शुरू कर दिया है। मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह हमें पाकिस्तान के बराबर भी नहीं मानते? हमने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है क्योंकि पाकिस्तान हमारे लिए एक दुष्ट और दुश्मन देश साबित हुआ है। हमें पानी देने से मना करने के आपके पास क्या कारण हैं। शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी और उमर पर पंजाब के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों ने देश की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारी कर्ज लिया है। उन्होंने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि हर बार पंजाब को सबसे ज्यादा अनुदान उठाना पड़ता है। हमारे राज्य से नदी का पानी छीन लिया गया। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने नदी के पानी का एक बड़ा हिस्सा राष्‍ट्र्‍थान को देकर पंजाब के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, जो एक गैर-तटीय राज्य है।

आतंकियों के...

इस रक्षा खरीद की कुल लागत 1981.90 करोड़ होगी। जिसमें भारतीय सेना के लिए इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम की खरीद की जाएगी। साथ ही लो लेवल लाइट वेट रडार, बहुत कम रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम जैसे लॉन्सर्ज और मिताइल आदि की खरीद की जाएगी। रक्षा मंत्रालय सेना के आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए रिमोटली पायलेटेड एयरियल व्हीकल, कई तरह के ड्रोन्स, बैलिस्टिक हेलमेट, भारी और मध्यम रेंज के क्लिक एरिक्शन फ्लाइटिंग व्हीकल और राइफलों के लिए नाइट विजन जैसे उपकरण खरीदेगा। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच की ऐतिहासिक बातचीत के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज यह देश इतिहास के अद्भुतपूर्व घटना को याद करने का स्वर्ण बन रहा है। एक ऐसी ऐतिहासिक घटना, जिसने न सिर्फ हमारे साक्ष्य बना आंदोलन को नई दिशा दी, बल्कि स्वतंत्रता के उद्देश्य को नए माथे दिए। सौ साल पहले श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की वो मुलाकात आज भी उतनी की प्रेरक है, उतनी ही प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 100 साल पहले वह मुलाकात, सामाजिक समरसता के लिए, विकसित भारत के सामूहिक लक्ष्यों के लिए आज की ऊर्जा के स्रोत की तरह है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं श्री नारायण गुरु को नमन करता हूँ और महात्मा गांधी जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, श्री नारायण गुरु के आदर्श पूरा मानवता के लिए बहुत बड़ी पूंजी हैं। जो लोग देश और समाज की सेवा के संकल्प पर काम करते हैं श्री नारायण गुरु उनके लिए प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। आप सभी जानते हैं कि समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग से मेरा क्या है और इसलिए आज भी जब मैं समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के लिए निर्णय लेता हूं तो मैं गुरु देव का जरूर याद करता हूं। पीएम मोदी ने कहा, भारत की विशेषता है कि हमारा देश जब भी मुश्किलों के भंवर में फंसता है, तो कोई न कोई महान विभूति देश के किसी कोने में जन्म लेकर समाज को नई दिशा दिखाता है। कोई समाज के आध्यात्मिक उत्थान के लिए काम करता है, तो कोई सामाजिक क्षेत्र में सामान्य सुधारों को गति देता है। श्री नारायण गुरु ऐसे ही महान संत थे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अभी हाल ही में हमने विश्व योग दिवस मनाया। इस बार योग दिवस की थीम थी, वन अर्थ, वन हेल्थ यानी एक धरती एक स्वास्थ्य। इससे पहले भी भारत ने विश्व कल्याण के लिए वन वर्ल्ड, वन हेल्थ जैसी पहल की है। आज भारत स्टोनेबेल डेवलपमेंट की दिशा में वन सन, वन वर्ल्ड, वन प्रिज जैसे ग्लोबल मूवमेंट को लीड कर रहा है। 2023 में जब भारत ने जी-20 समिट को लीड किया था, तब थीम रखा था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हमारे इन प्रयासों में वसुधैव कुटुम्बक की धारणा जुड़ी हुई है।

आतंकवाद के खिलाफ...

बेकम ने डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मायदो को भी छोड़ने का आह्वान किया। पाकिस्तान में आतंकवादियों को निशाना बनाने वाले भारतीय सेना के सैन्य अभियान अपरेशन सिंदूर को लेकर एनएसए ने कहा, भारत की कार्रवाई नपी-तुली थी और संसर्प को बढ़ावा देने वाली नहीं थी। उन्होंने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने का भी आह्वान किया।

इससे पहले, डोभाल ने रूसी रक्षा परिषद के उपसचिव अलेक्जेंडर डेवित्सोव के साथ भी एसओए की सुरक्षा परिषद के सचिवों की 20वीं बैठक के दौरान मुलाकात की। दोनों देशों ने आपसी संबंध, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की। रूसी पक्ष ने कहा कि वह जल्द ही रणनीतिक वार्ता के अगले दौर के लिए डोभाल का रूप में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। दोनों पक्षों ने भारत और रूस के बीच विश्लेषण रणनीतिक साझेदारी के आधार पर आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने की जोर दिया।

डोभाल ने सोमवार को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और विदेश मंत्री वांग यी से भी मुलाकात की थी। इस दौरान डोभाल ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय (एमईए) की ओर से जारी बयान के मुताबिक, दोनों पक्षों ने भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों

मेरे हाल के घटनाक्रम की समीक्षा की। साथ ही आपसी रिश्तों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर भी चर्चा हुई ताकि दोनों देशों के संबंध मजबूत हो सकें। बैठक में डोभाल ने साफ कहा कि आतंकवाद का कोई भी रूप बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और इसके खिलाफ सख्त कदम उठाना जरूरी है ताकि पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रह सके।

चीन के विदेश मंत्री वांग यी से हुई बातों में भारत के एनएसए अजित डोभाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत को आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। डोभाल का बयान पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान को खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग की मांग करता रहा है और स्वाभाविक है कि चीन जैसे प्रभावशाली देशों से इस दिशा में समर्थन की अपेक्षा की जाए।

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने चीन की ओर से भारत के साथ संबंधों को सुधारने की इच्छा जताई। इससे संकेत मिलता है कि चीन, जो हाल के वर्षों में भारत के साथ सीमा विवादों और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में उलझा रहा है, अब संबंधों को स्थिरता की ओर ले जाने के प्रयास कर रहा है। आज के भूराजनीतिक वातावरण में डोभाल और वांग यी की यह मुलाकात सकारात्मक संकेत दे रही हैं। हालांकि भारत-चीन संबंधों में कई जटिलताएं अपनी जगह कायम हैं। विशेषकर सीमा विवाद, व्यापार असंतुलन और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में। फिर भी, दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने और द्विपक्षीय संवाद को आगे बढ़ाने की बात कही है। यह एक ऐसा संकेत है जो संभावता है कि दोनों देश तनाव को कम करने और संवाद के माध्यम से समाधान खोजने के इच्छुक हैं।

विशेषज्ञों का नजर में भारत की दृष्टि से डोमाल और वांग या कौन सी ही एक वैश्विक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटा रहा है। उस दिशा में इस वार्ता की एक कूटनीतिक मौका माना जा सकता है। चीन के साथ संवाद बनाए रखना भी आवश्यक है, विशेषकर ऐसे समय में जब वैश्विक धुवीकरण बढ़ रहा है। पश्चिम एशिया में भारत को संतुलित भूमिका के साथ आगे बढ़ना है। ध्यान रखना है कि भारत के ईरान और इजराइल दोनों से रणनीतिक संबंध हैं। कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि डोमाल-वांग या वार्ता केवल एक द्विपक्षीय बैठक नहीं थी, बल्कि यह एक व्यापक रणनीतिक संवाद था जो एशिया की सुरक्षा, स्थिरता और कूटनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। आतंकवाद के खिलाफ साझा रुख, संबंधों को सुधारने की इच्छा और वैश्विक संकटों पर समन्वय की संभावना, ये सभी आयाम संकेत करते हैं कि भारत और चीन, प्रतिस्पर्धा के बावजूद, उस और सहयोग के रास्ते तलाशने को तैयार हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के किंगदाओ में बुधवार से रहें। एससीओ (शंघाई कोऑपेरेशन ऑर्गनाइजेशन) में शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन में राजनाथ सिंह आतंकवाद का मुद्दा उठाएंगे। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में हुए संघर्ष के बाद यह किसी शीर्ष भारतीय नेता की पहली चीन यात्रा है। एससीओ सम्मेलन में रक्षा मंत्री एससीओ के सदस्य देशों के बीच व्यापार, आर्थिक सहयोग और संपर्क बढ़ाने की भी वकालत कर सकते हैं। रक्षा मंत्री चीन में कई सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ ट्रिपलसी मुलाकात कर सकते हैं। इनमें चीन और रूस के रक्षा मंत्री भी शामिल हैं।

बिहार में लगेगा...

बिहार से बिजली स्टोरेज के लिए 1000 मेगावाट के लिए मांग की गई है। अगले 6 महीने में अतिरिक्त 500 मेगावाट की सप्लाई कर दी जाएगी। देश में जरूरत के अनुसार बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। हैकेंद्रीय मंत्री मनोहर ने कहा कि भारत पहले पावर डिफिसिट देश के नाम से जाना जाता था, लेकिन हम आज बिजली की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। उसके साथ-साथ भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल को बिजली निर्यात भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। देश में थर्मल पावर, सौर, विंड पावर और स्टोरेज के प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं। बैठक में सभी राज्यों में कम से कम एक परमाणु बिजली घर का निर्माण करने को लेकर योजना बनाई गई है। साल 2035 तक पावर सेक्टर के लिए विजान तैयार किया गया है। जिसे तय समय में एनडीए सरकार में पूरा किया जाएगा। सम्मेलन में बिहार, झारखंड, ओड़ीशा, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान-निकोबार के ऊर्जा मंत्री भी शामिल हुए।

देशभर में पासपोर्ट...

तान प्रमुख स्तम्भ हैं, जो हम विकासत भारत को आर ल जाएंगे। ये सभी हमारे पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम में साफ तौर पर दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में पासपोर्ट सुविधाओं में बदलाव आया है, जिसमें 2014 में 91 लाख से बढ़कर 2024 में 1.46 करोड़ पासपोर्ट जारी किए गए हैं। मंत्री ने बताया कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम संस्करण 2.0 को पहले ही पूरे देश में शुरू किया जा चुका है, जिसमें दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए उच्च-स्तरीय, उपरती हुई तकनीकें शामिल हैं। उन्होंने कहा, नागरिक-केंद्रित सेवा के अगले स्तर के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने पूरे देश में झड़्ड 2.0 को शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल पीएसपी तालिका पायलट परीक्षण भी चल रहा है। इसे सभी भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में चरणों में लागू किया जाएगा। जयशंकर ने ई-पासपोर्ट पहल को एक बड़ी उपलब्धि बताया। यह संपर्क रहित चिप-आधारित डेटा रीडिंग के साथ यात्रा को आसान बनाता है और आब्रजन (इमिग्रेशन) मंजूरी में तेजी लाता है। उन्होंने एमपासपोर्ट पहल के कोलॉन्क की हवाला दिया, जिसने 25 लाखों और पुलिस शासित प्रदेशों में पुलिस स्थानाणन समय को 5-7 दिनों कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल 10 नए पोस्ट ऑफिस

मोरपंख बीमारी से निपटने में भी काफी कारगर है। सभी तरह के उपायों के बाद भी यदि बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है तो बीमारी से संबंधित कागजातज के बीच में मोरपंख रख दें। जल्द ही इसके बेहतर परिणाम दिखाई देंगे। घर के ड्राइंग रूम या डाइनिंग रूम में 11, 15 या इससे ज्यादा मोरपंख एकसाथ लगाने से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य अच्छा होता है और स्नेह बना रहता है। मोरपंख घर के स्वच्छ और बेहतर वातावरण प्रदान करने में भी सहायक है। जिस जगह पर मोरपंख लगा हो उस जगह के आसपास कीड़े-मकोड़े नहीं रहते हैं। धन की समस्या के समाधान के लिए आग्नेय कोण में कम के कम 5 फीट की उंचाई पर दो मोरपंखी शुक्ल पक्ष में लगायें, धन से जुड़ी समस्या का समाधान होगा। मोरपंख के कुछ सावधानी बरतना भी जरूरी है। कभी भी घर में खंडित मोरपंख का उपयोग ना करें, इससे सही परिणाम नहीं मिल पाएंगे।

को थपपड मारने के केस में चार्ज बहस पूरी हो चुकी है, जिसमें हाईकोर्ट से नरेश मीणा को जमानत भी मिल चुकी है।

गौरतलब है कि 13 नवंबर 2024 को देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र के समरावता गांव में उपचुनाव के दौरान मतदान का बहिष्कार हुआ था।

निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठा था और पोलिंग बूथ में घुसने की कोशिश के दौरान अमित चौधरी को थपपड मारने का आरोप भी उन पर लगा। रात में पुलिस नरेश को पकड़ने गांव पहुंची तो वहां ग्रामीणों से झड़प हो गई। कई वाहनों में आगजनी हुई, हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज, हवाई फायर और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा।

उपराष्ट्रपति पहुंचे मुजफ्फरपुर, कहा—

प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों पर जोर देना चाहिए

पटना (एजेंसियां)।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज बिहार दौरे पर पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट पर सीएम नीतीश कुमार ने उपराष्ट्रपति पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के भी कई वरीय नेताओं ने भी उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। इसके बाद वह मुजफ्फरपुर रवाना हो गए। मुजफ्फरपुर में एल एन मिश्रा मैनेजमेंट कॉलेज के 24वें स्थापना दिवस समारोह में उपराष्ट्रपति ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया।

इस अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता और मंत्री नीतीश मिश्र ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उपराष्ट्रपति ने पूर्व सीएम स्वर्गीय डॉ. जगन्नाथ मिश्रा को श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदानों को याद



किया और बिहार के गौरवशाली इतिहास की चर्चा की। अपने संबोधन में उप राष्ट्रपति ने कहा कि बिहार की धरती धर्म और ज्ञान की भूमि रही है, जिसने देश को अनेक मनीषी, क्रांतिकारी और चिंतक दिए हैं।

इस समारोह में बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ

दिनेश चंद्र राय भी उपस्थित रहे। उन्होंने कॉलेज की उपलब्धियों और उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बारे में चर्चा की। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि वही उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस भूमि पर आकर मुझे नई ताकत और ऊर्जा की अनुभूति हो रही

है। बिहार की जनता का उत्साह, ज्ञान और चेतना पूरे देश के लिए प्रेरणादायी है। आज शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। साथ ही हमें प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों पर जोर देना चाहिए।

उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सराहना करते हुए कहा

कि यह नीति छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। धनखड़ ने अपने संसदीय जीवन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिताए समय को भी याद किया और उनके संसदीय अनुभवों की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने पहली बार पहलगाम और 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने आपातकाल के दौर को याद करते हुए कहा कि उस समय लोकतंत्र को दबाने का प्रयास किया गया था लेकिन अब यह जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चली संपूर्ण क्रांति ने भारत में लोकतंत्र को नई ऊर्जा और दिशा दी। उपराष्ट्रपति ने छात्रों को अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया।

दिविजय सिंह की 15वीं पुण्यतिथि पर सीएम नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि



जमुई (एजेंसियां)।

दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री दिविजय सिंह की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड अंतर्गत नयागांव स्थित उनके समाधि स्थल पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने माल्यार्पण कर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री सुमित सिंह, पूर्व सांसद पुतुल कुमारी और जमुई विधायक श्रेयसी सिंह सहित कई अन्य नेता भी उपस्थित रहे। सभी नेताओं ने दिवंगत नेता

की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री का यह दौरा लगभग 25 मिनट का रहा, जिसके बाद वे पटना के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हेलिपैड से कार्यक्रम स्थल की दूरी लगभग 3 किलोमीटर रही, इस दौरान पूरे इलाके में वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई थी। मुंगेर जेल के जमुई, लखीसराय, शेखपुरा और मुंगेर जिलों से बड़ी संख्या में पुलिस बल और बीएसपी की तैनाती की गई थी। जगह-जगह बैरिकेड्स लगाए गए थे और

आने-जाने वालों की मेटल डिटेक्टर से जांच की गई। इस मौके पर दिवंगत नेता की पत्नी व पूर्व बांका सांसद पुतुल कुमारी, पुत्री मानशी सिंह, झाड़ा विधायक दामोदर राबत, पूर्व विधायक रविंद्र मंडल, जिलाधिकारी नवीन कुमार, एसपी विश्वजीत दयाल सहित कई प्रशासनिक और राजनीतिक हस्तियां मौजूद थीं। हालांकि मुख्यमंत्री से मिलने की उम्मीद में बड़ी संख्या में लोग सड़कों के किनारे जुटे थे, लेकिन उन्होंने अपने वाहन से ही लोगों का अभिवादन किया और सीधे हेलिपैड की ओर प्रस्थान कर गए।

150 साल पुराने मंदिर से अष्टधातु की मूर्तियां चोरी, श्रद्धालुओं में आक्रोश

पुर्णिया (एजेंसियां)।

कटिहार जिले के गेराबारी बस्ती में स्थित लगभग 150 साल पुराने ठाकुरबाड़ी मंदिर से अष्टधातु की बेशकीमती मूर्तियों की चोरी ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। चोरी हुई मूर्तियों में प्रभु श्रीराम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी की प्रतिमाएं शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर में ग्रामीणों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है और यह सिर्फ मूर्तियों की चोरी नहीं, बल्कि उनकी आस्था और भावना पर हमला है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, चोरी हुई मूर्तियों और उनके सिंहासन का कुल वजन दो कुंटल



से अधिक था, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि यह कार्य एक अकेले व्यक्ति का नहीं हो सकता। ग्रामीणों का मानना है कि यह एक सुनियोजित साजिश है, जिसमें कई लोग शामिल थे और इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय भी लगा होगा।

स्थानीय लोगों ने घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस से विशेष जांच टीम गठित करने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी

दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मंदिर परिसर और उसके आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि जल्द ही मूर्तियों को बरामद कर लिया जाएगा और दोषियों को कानून के हवाले किया जाएगा।

छपरा (एजेंसियां)।

छपरा में मशरख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. संजय कुमार को स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और झूठे जख्म प्रतिवेदन जारी करने, सरकारी दवाओं के दुरुपयोग और खून की जांच में आवश्यक केमिकल की अनुपलब्धता जैसे गंभीर आरोपों के आधार पर निलंबित कर दिया है।

मशरख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. संजय कुमार को स्वास्थ्य विभाग ने गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और



झूठे जख्म प्रतिवेदन जारी करने, सरकारी दवाओं के दुरुपयोग और खून की जांच में आवश्यक केमिकल की अनुपलब्धता जैसी गंभीर लापरवाहियों के आरोप हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराई गई प्रारंभिक जांच में इन आरोपों को प्रथम दृष्टया सत्य पाया गया, जिसके बाद यह कड़ी कार्रवाई की

गई। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, डॉ. संजय कुमार की कार्यप्रणाली ने न केवल सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए, बल्कि स्वास्थ्य विभाग की साख को भी नुकसान पहुंचाया।

स्थानीय लोगों महेश्वर सिंह, रंजन कुमार सिंह सहित कई अन्य

ने प्रभारी चिकित्सक पर ला-परवाही, अधीनस्थ कर्मियों की संलिप्तता से फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने, केमिकल की अनुपलब्धता और दवाओं के दुर्विनियोग जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इसी आधार पर विभाग ने दो सदस्यीय जांच समिति गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट में कार्रवाई की सिफारिश की गई।

इस निलंबन के बाद क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर जनता में गहरी चिंता है। लोगों का कहना है कि जब सरकारी अस्पतालों में ही फर्जीवाड़ा होगा तो भरोसा किस पर किया जाए।

विभागीय सूत्रों के अनुसार, अब इस मामले की विस्तृत जांच

के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है, जो पूरे स्वास्थ्य केंद्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा करेगी और अन्य कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। निलंबन की अवधि में डॉ. संजय कुमार को जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा और उनका मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग, पटना निर्धारित किया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आम लोगों के स्वास्थ्य और अधिकारों से किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इस कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है और अन्य पदाधिकारी भी सतर्क हो गए हैं।

बिहार में शिक्षा विभाग की लापरवाही उजागर शिक्षकों का तबादला निजी स्कूलों में

पश्चिम चंपारण (एजेंसियां)।

पश्चिम चंपारण में शिक्षा विभाग की ओर से जारी ऐच्छिक स्थानांतरण आदेश में गंभीर अनियमितता सामने आई है। विभाग ने कई सरकारी शिक्षकों का तबादला ऐसे विद्यालयों में कर दिया है, जो निजी प्रबंधन के अधीन संचालित होते हैं। इससे न केवल संबंधित शिक्षक भ्रम की स्थिति में पड़ गए हैं, बल्कि विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

घटना चनपटिया अंचल क्षेत्र की है, जहां चूहड़ी बाजार स्थित लोथला मिडिल स्कूल (जो कि एक निजी शिक्षण संस्थान है) में दो शिक्षिकाओं, पूजा कुमारी और



फर्नाज खातून का स्थानांतरण कर दिया गया। जब दोनों शिक्षिकाएं विद्यालय में योगदान देने पहुंचीं तो उन्हें पता चला कि यह स्कूल सरकारी नहीं है, बल्कि निजी संस्था द्वारा संचालित होता है। इस गलती की जानकारी मिलने के बाद विभागीय अधिकारी

हकत में आए। स्थापना डीपीओ कुमार अनुभव ने स्वीकार किया कि यह चूक तबादला सूची में मौजूद तकनीकी विसंगति के कारण हुई है। उन्होंने बताया कि मामले में उच्च शिक्षा पदाधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा गया है और जल्द ही संशोधित

आदेश जारी किए जाएंगे।

इसी अंचल के भरपटिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी स्थानांतरण को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

पहले से ही यहां कक्षा 1 से 12 तक के लिए 32 शिक्षक-शिक्षिकाएं कार्यरत हैं। हालिया स्थानांतरण आदेश के तहत यहां 11 और शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है, जिनमें से तीन ने यो-गदान भी कर दिया है।

हालांकि विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभु राम ने इसे छात्र संख्या के अनुपात में उचित ठहराया है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में वर्तमान में 1150 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं और

अधिक शिक्षकों की तैनाती से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इस पूरे घटनाक्रम से शिक्षक समुदाय में असंतोष व्याप्त है। कई शिक्षक, जिन्हें अब तक सरकारी स्कूलों में सेवा देनी थी, निजी विद्यालयों में तबादला आदेश पाकर असमर्थता जता रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग द्वारा बिना आधारभूत जांच के जारी किए गए आदेश उन्हें मानसिक तनाव में डाल रहे हैं। अब यह देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस गलती को कितनी शीघ्रता और प्रभावशीलता से दुरुस्त करता है। फिलहाल, विभाग की साख पर सवाल उठना तय माना जा रहा है।

टीएमबीयू में लगाई गई तिलकामांझी की भव्य प्रतिमा, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी अनावरण



भागलपुर (एजेंसियां)।

तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद तिलकामांझी की 8 फीट ऊंची और करीब 800 किलो वजनी कांस्य प्रतिमा विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित की जा चुकी है। इस प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होने की संभावना है, जिन्हें जुलाई माह में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आमंत्रित किया गया है।

यह भव्य कांस्य प्रतिमा राजस्थान के जयपुर स्थित प्रसिद्ध सुतार परिवार द्वारा बेहद कलात्मक ढंग से निर्मित की गई है। इसे विश्वविद्यालय के तिलकामांझी पार्क में विशेष चबूतरे पर स्थापित किया जा रहा है। चबूतरे सहित प्रतिमा की कुल

ऊंचाई लगभग 18 फीट होगी, जो दूर से ही दिखाई देगी। विश्वविद्यालय प्रशासन इस ऐतिहासिक क्षण को और भी खास बनाने के लिए अमर शहीद तिलकामांझी की स्मृति में एक विशेष स्मारिका भी प्रकाशित करेगा। साथ ही 'तिलकामांझी पीठ' की स्थापना की भी योजना बनाई गई है, ताकि क्षेत्रीय इतिहास और शोध को प्रोत्साहन मिल सके।

प्रतिमा के साथ-साथ तिलकामांझी पार्क में एक एम्फीथिएटर का निर्माण भी तेज़ी से जारी है। पूरी परियोजना पर लगभग एक करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, जिसमें स्थानीय जनसहयोग के साथ-साथ एनटीपीसी, कहलगांव द्वारा भी आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है।

राष्ट्रपति के संभावित दौरे को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारत सरकार भी मामले पर नज़र रखे हुए हैं। विश्वविद्यालय से उसकी ऐतिहासिक विरासत, प्रमुख उपलब्धियों और शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, जिसे तैयार किया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि लगभग 32 वर्षों बाद टीएमबीयू अपने नामकरण को सही मायनों में सार्थक करने जा रहा है। इस आयोजन को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन, अधिकारी, कर्मचारी और भागलपुर की जनता बेहद उत्साहित हैं और राष्ट्रपति मुर्मू के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह क्षण न सिर्फ टीएमबीयू बल्कि पूरे अंग प्रदेश और बिहार के लिए गौरव का विषय बन गया है।